

EXAM GENIUS

Presents

MONTHLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

FEBRUARY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and capital requirements?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और पूंजी आवश्यकता की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव क्यों दिया है?

- A) To align India's FX risk norms with global standards and ensure uniformity / भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और एकरूप बनाने के लिए
- B) To promote higher foreign currency lending / विदेशी मुद्रा ऋण को बढ़ावा देने के लिए
- C) To reduce banks' capital burden on FX exposure / एफएक्स जोखिम पर बैंकों का पूंजी बोझ कम करने के लिए
- D) To exempt small banks from FX risk regulations / छोटे बैंकों को एफएक्स जोखिम नियमों से छूट देने के लिए
- E) To postpone implementation of FX risk norms indefinitely / एफएक्स जोखिम नियमों के क्रियान्वयन को अनिश्चितकाल तक टालने के लिए

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and the associated capital requirements.
- आरबीआई ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और उससे जुड़ी पूंजी आवश्यकताओं की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।
- The objective is to align India's FX risk norms with global standards prescribed by the Basel Committee and ensure uniform implementation across all regulated entities.
- इसका उद्देश्य बेसल समिति द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को बनाना और सभी विनियमित संस्थाओं में एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

- Under the proposed framework, banks will be required to maintain a minimum capital charge of 9% on their net open foreign exchange positions.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत, बैंकों को अपने शुद्ध खुले विदेशी मुद्रा जोखिम पर न्यूनतम 9% की पूंजी रखना अनिवार्य होगा।
- The RBI has invited public feedback on these proposals.
- आरबीआई ने इन प्रस्तावों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। (फीडबैक)
- The proposed changes are expected to come into effect from 1 April 2027.
- ये प्रस्तावित बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना है।

Ques: What key insight was revealed by SEBI's survey on Indian households' participation in the securities market?

भारतीय घरों की प्रतिभूति बाज़ार में भागीदारी को लेकर सेबी (SEBI) के सर्वेक्षण से कौन-सा प्रमुख तथ्य सामने आया?

- A) More than 50% households actively invest in equities and bonds / आधे से अधिक घर इक्विटी और बॉन्ड में सक्रिय निवेश करते हैं
- B) Awareness and participation levels are almost equal / जागरूकता और भागीदारी का स्तर लगभग समान है
- C) Only about 9.5% of Indian households participate despite higher awareness / उच्च जागरूकता के बावजूद केवल लगभग 9.5% घर ही भागीदारी करते हैं
- D) Rural households have higher participation than urban households / ग्रामीण घरों की भागीदारी शहरी घरों से अधिक है
- E) Participation is highest in complex instruments like derivatives and AIFs / डेरिवेटिव्स और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी सबसे अधिक है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- A SEBI survey revealed that out of 33.72 crore Indian households, only 3.21 crore households (9.5%) invest in securities such as equities, mutual funds, and

corporate bonds.

- सेबी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 33.72 करोड़ भारतीय घरों में से केवल 3.21 करोड़ घर (9.5%) ही इक्विटी, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे प्रतिभूति बाज़ार में निवेश करते हैं।

- Although 63% households (around 21.3 crore) are aware of at least one market-linked product, actual participation remains very low at 9.5%.

- लगभग 63% घर करीब)21.3 करोड़संबंधित उत्पाद के बारे -कम से कम एक बाज़ार (में जागरूक हैं, लेकिन वास्तविक भागीदारी केवल 9.5% ही है।

- The survey was conducted by Kantar between May and July 2025, covering over 90,000 households across 400 cities and 1,000 villages.

- यह सर्वेक्षण कांतर)Kantar) द्वारा मई से जुलाई 2025 के बीच किया गया, जिसमें 400 शहरों और 1,000 गांवों के 90,000 से अधिक घर शामिल थे।

- Nearly 30.51 crore households remain outside the securities market, highlighting significant under-penetration despite strong market growth over the past decade.

- लगभग 30.51 करोड़ घर अब भी प्रतिभूति बाज़ार से बाहर हैं, जो पिछले एक दशक में तेज़ बाज़ार वृद्धि के बावजूद कम पहुंच को दर्शाता है।

- Awareness is highest for mutual funds (53%) and ETFs (49%), while participation in complex instruments like corporate bonds, derivatives, REITs, InvITs, and AIFs is extremely limited.

- म्यूचुअल फंड (53%) और ETF (49%) के प्रति जागरूकता सबसे अधिक है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, REITs, InvITs और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी बहुत सीमित है।

- Urban households show higher awareness (74%) compared to rural households (56%), reflecting clear geographic disparities.

- शहरी घरों में जागरूकता (74%) ग्रामीण घरों (56%) की तुलना में अधिक पाई गई, जो भौगोलिक असमानता को दर्शाती है।

Ques: What is the key objective of the newly launched Aadhaar App dedicated to the nation?

राष्ट्र को समर्पित नए आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To replace physical Aadhaar cards completely / भौतिक आधार कार्ड को पूरी तरह से बदलना
- B) To provide a secure, convenient and privacy-first digital identity platform / सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयताप्रथम डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म प्रदान करना-
- C) To enable only biometric authentication for all services / सभी सेवाओं के लिए केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करना
- D) To store Aadhaar numbers with service providers / सेवा प्रदाताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत करना
- E) To limit Aadhaar usage to government services only / आधार के उपयोग को केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Minister of State for Commerce and Industry and Electronics & Information Technology, Shri Jitin Prasada, dedicated the new Aadhaar App to the nation.
- वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने नए आधार ऐप को राष्ट्र को समर्पित किया।
- The Aadhaar App has been developed by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as a next-generation mobile application.
- आधार ऐप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक नेक्स्ट-जेनरेशन मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है।
- It provides Aadhaar Number Holders with a secure, convenient and privacy-first way to carry, share, show and verify their digital identity.
- यह आधार संख्या धारकों को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयताआधारित तरीके से रखने-, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने की सुविधा देता है।
- The app supports multiple real-life use cases such as hotel check-ins via OVSE QR code scanning, optional face verification, age verification for cinema tickets, hospital admissions, and verification of gig workers.
- यह ऐप OVSE क्यूआर कोड के माध्यम से होटल चेकइन-, वैकल्पिक फेस

वेरिफिकेशन, सिनेमा टिकट के लिए आयु सत्यापन, अस्पताल प्रवेश और गिग वर्कर्स के सत्यापन जैसे कई वास्तविक उपयोग मामलों को सपोर्ट करता है।

- Advanced features include face verification for proof of presence, one-click biometric lock/unlock, viewing authentication history, and a QR-based contact card.

- उन्नत सुविधाओं में उपस्थिति प्रमाण के लिए फेस वेरिफिकेशन, एकक्लिक - बायोमेट्रिकलॉकअनलॉक/, प्रमाणीकरण इतिहास देखना और क्यूआरआधारित - कॉन्टैक्ट कार्ड शामिल हैं।

- The app allows management of up to five Aadhaar profiles on one device under the concept of “One Family – One App” and enables mobile number updates along with address updates.

- यह ऐप “वन फैमिली – वन ऐप” की अवधारणा के तहत एक डिवाइस पर पाँच तक आधार प्रोफाइल प्रबंधित करने की सुविधा देता है तथा पते के साथसाथ मोबाइल नंबर - अपडेट करने की भी अनुमति देता है।

- It ensures data minimisation by sharing only digitally signed verifiable credentials and not storing Aadhaar numbers with verifiers, in line with the DPDP Act.

- यह सत्यापनकर्ताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत न कर केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण साझा कर डेटा न्यूनतमकरण सुनिश्चित करता है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के अनुरूप है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years till May 01, 2029?

फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में तीन वर्ष 01 मई 2029 तकके कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है (?)

- A) Rajesh Kumar / राजेश कुमार
- B) Deepak Mehta / दीपक मेहता
- C) Anil Sharma / अनिल शर्मा
- D) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- E) Rishi Gupta / ऋषि गुप्ता

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Mr. Rishi Gupta has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years until May 01, 2029.
- श्री ऋषि गुप्ता को फिनो पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीन वर्ष के लिए 01 मई 2029 तक (नियुक्त किया गया है)।
- Fino Payments Bank has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) for conversion into a Small Finance Bank, becoming the first among payments banks to receive such approval.
- फिनो पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है।
- Fino Payments Bank was established in 2015 and its headquarters is located in Navi Mumbai.
- फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है।
- The tagline of Fino Payments Bank is “Qadar Aapki Mehnat Ki”.
- फिनो पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन “कदर आपकी मेहनत की” है।

Ques: Why did the Department of Posts (DoP) sign an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL)?

डाक विभाग (DoP) ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता क्यों किया?

- A) To introduce postal savings bonds / डाक बचत बांड शुरू करने के लिए
- B) To promote access to regulated capital market services for citizens / नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए
- C) To privatize selected post offices / चयनित डाकघरों का निजीकरण करने के लिए
- D) To replace banks with post offices for all investments / सभी निवेशों के लिए बैंकों को डाकघरों से बदलने के लिए
- E) To launch a new digital currency platform / नया डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म शुरू

करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, Government of India, signed an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL) to promote access to regulated capital market services for citizens across the country.
- भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (DoP) ने नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता किया है।
- India Post, with its extensive nationwide network of over 1.65 lakh post offices, including a strong presence in rural and remote areas, plays a key role in extending financial services to underserved populations.
- 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक राष्ट्रीय नेटवर्क और ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण इंडिया पोस्ट वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Under the agreement, citizens will be able to access SSL's services through digital utilities such as onboarding links and QR codes available on official platforms and at selected post offices.
- इस समझौते के तहत नागरिक आधिकारिक प्लेटफॉर्म और चयनित डाकघरों पर उपलब्ध ऑनबोर्डिंग लिंक और क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए SSL की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- The services include opening demat and trading accounts, investing in mutual funds, participating in IPOs, and accessing other permitted investment products.
- इन सेवाओं में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, आईपीओ में भागीदारी और अन्य अनुमत निवेश उत्पाद शामिल हैं।

Ques: What is the maximum timeline prescribed by RBI for banks to take credit decisions on loans up to ₹25 lakh for Micro and Small Enterprises?

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ₹25 लाख तक के ऋण पर क्रेडिट निर्णय लेने हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा क्या है?

- A) 7 working days
- B) 10 working days
- C) 14 working days
- D) 21 working days
- E) 30 working days

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The investment and turnover limits for classification of MSMEs have been revised to enable higher efficiency of scale, technology upgradation, better access to capital, and global competitiveness.
- एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में संशोधन किया गया है ताकि बड़े पैमाने की दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी तक बेहतर पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
- As per RBI (informed by DFS), for loans up to ₹25 lakh to Micro and Small Enterprises, banks must take credit decisions within 14 working days.
- डीएफएस द्वारा सूचित आरबीआई के अनुसार, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ₹25 लाख तक के ऋण के लिए बैंकों को 14 कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेना होगा।
- For loans above ₹25 lakh, timelines will follow board-approved sanction time norms of banks.
- ₹25 लाख से अधिक के ऋण के लिए समय-सीमा बैंकों के बोर्ड-अनुमोदित स्वीकृति मानकों के अनुसार होगी।
- Banks are required to prominently display MSME credit-related information, timelines, and indicative document checklists on their websites.
- बैंकों को एमएसएमई से जुड़े क्रेडिट विवरण, समय-सीमा और दस्तावेज़ सूची अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- Under CGTMSE, loan applications, sanctions, and disbursements under the Credit Guarantee Scheme (CGS) for MSEs are monitored quarterly by the Empowered Committee on MSME chaired by RBI along with SLBCs.
- सीजीटीएमएसई के तहत, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGS) में ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण की तिमाही निगरानी आरबीआई अध्यक्षता वाली एमएसएमई सशक्त समिति और एसएलबीसी द्वारा की जाती है।

- The credit guarantee cover for MSEs has been enhanced from ₹5 crore to ₹10 crore with effect from 01.04.2025 under CGS.
- सीजीएस के तहत एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।

**Ques: Which bank has received RBI approval to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gujarat?
किस बैंक को गुजरात के GIFT सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में शाखा खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?**

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Punjab & Sind Bank has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.
- पंजाब एंड सिंध बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के IFSC में शाखा खोलने की अनुमति मिली है।
- GIFT City IFSC is India's premier international financial hub, created to facilitate cross-border financial transactions.
- GIFT सिटी IFSC भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जिसे सीमा-पार वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
- It provides a world-class ecosystem for international trade finance, offshore banking, and capital market activities.
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, ऑफशोर बैंकिंग और पूंजी बाज़ार गतिविधियों के लिए विश्वस्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है।

About Punjab & Sind Bank :

- Established : 1908
 - HQ : New Delhi
 - MD & CEO : Swarup Kumar Saha
 - Tagline : Where service is a way of life
-

Ques: As per the revised World Bank International Poverty Line, what was India's extreme poverty rate in 2022–23?

संशोधित विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार 2022–23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी?

- A) 3.1%
- B) 4.5%
- C) 5.3%
- D) 12.9
- E) 23.9%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has revised the International Poverty Line (IPL) from USD 2.15 to USD 3.00 per day, adjusted for 2021 Purchasing Power Parity (PPP).
- विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को USD 2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर USD 3.00 प्रति दिन कर दिया है, जो 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) के अनुसार समायोजित है।
- The revision accounts for changes in global price levels and consumption patterns.
- यह संशोधन वैश्विक मूल्य स्तर और उपभोग पैटर्न में आए बदलावों को दर्शाता है।
- According to the revised IPL, India's extreme poverty rate in 2022–23 stood at 5.3%.
- संशोधित IPL के अनुसार, वर्ष 2022–23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% रही।
- India's lower-middle-income poverty rate in 2022–23 was estimated at 23.9%.
- 2022–23 में भारत की निम्न-मध्यम आय वर्ग गरीबी दर 23.9% आंकी गई।
- These estimates are highlighted in the Economic Survey.
- ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं।

Ques: In which locations will the pilot project of CBDC-based “digital food currency” under the free ration scheme be rolled out?

मुफ्त राशन योजना के तहत CBDC आधारित “डिजिटल फूड करेंसी” की पायलट परियोजना किन स्थानों पर शुरू की जाएगी?

- A) Chandigarh, Puducherry and three districts of Gujarat / चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिले
- B) Delhi, Mumbai and Chennai / दिल्ली, मुंबई और चेन्नई
- C) Gujarat and Rajasthan only / केवल गुजरात और राजस्थान
- D) All Union Territories of India / भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश
- E) Punjab, Haryana and Himachal Pradesh / पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India is set to roll out a pilot project for Central Bank Digital Currency (CBDC), also called “digital food currency”, under the free ration scheme.
- भारत सरकार मुफ्त राशन योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) यानी “डिजिटल फूड करेंसी” का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
- The pilot will be implemented in Chandigarh, Puducherry, and three districts of Gujarat.
- यह पायलट चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिलों में लागू किया जाएगा।
- Beneficiaries will receive monthly digital food coupons directly into an RBI-enabled digital wallet on their mobile phones.
- लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर RBI-सक्षम डिजिटल वॉलेट में मासिक डिजिटल फूड कूपन मिलेंगे।
- Coupons can be redeemed at ration shops by scanning the QR code of the shop owner to obtain free foodgrains.
- राशन दुकानदार के QR कोड को स्कैन कर कूपन भुनाए जा सकेंगे और निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा।
- A soft launch was conducted earlier in Ahmedabad with 25 beneficiaries.

- इससे पहले अहमदाबाद में 25 लाभार्थियों के साथ इसका सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।
- The next phase will cover Anand, Sabarmati and Dahod districts of Gujarat.
- अगले चरण में गुजरात के आणंद, साबरमती और दाहोद जिलों को शामिल किया जाएगा।

Ques: Who has issued draft guidelines on resolution plans for borrowers affected by natural disasters?

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाओं पर मसौदा दिशानिर्देश किसने जारी किए हैं?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) National Disaster Management Authority / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- C) State Governments / राज्य सरकारें
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft guidelines for banks and other regulated entities on resolution plans during natural disasters.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाधान योजनाओं को लेकर बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- The framework will be applicable from April 1, and RBI has invited public and stakeholder feedback until February 17.
- यह ढांचा 1 अप्रैल से लागू होगा और RBI ने 17 फरवरी तक सार्वजनिक एवं हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
- The proposed framework requires banks to proactively plan for natural calamities while framing their credit policies, instead of relying on ad hoc relief measures.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत बैंकों को तदर्थ राहत उपायों के बजाय क्रेडिट नीतियाँ बनाते समय प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजना बनानी होगी।
- Banks will need to assess climate risks in advance and prepare pre-defined

resolution mechanisms.

- बैंकों को जलवायु जोखिमों का पूर्व मूल्यांकन कर पूर्व-निर्धारित समाधान तंत्र तैयार करना होगा।
- RBI has clarified that only standard borrowers will be eligible for relief.
- RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मानक (स्टैंडर्ड) उधारकर्ता ही राहत के पात्र होंगे।
- Borrowers who have not defaulted for more than 30 days at the time of the disaster will qualify for relief.
- आपदा के समय जिन उधारकर्ताओं ने 30 दिनों से अधिक की चूक नहीं की है, वे राहत के लिए पात्र होंगे।

Ques: At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at what percentage of the FY26 Budget Estimate?

दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा FY26 के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत था?

- A) 48.0%
- B) 50.2%
- C) 52.8%
- D) 54.5%
- E) 56.7%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at ₹8.55 lakh crore, which was 54.5% of the FY26 Budget Estimate.
- दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.55 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के बजट अनुमान का 54.5% था।
- This level was lower than the 56.7% of the annual target recorded during the same period in the previous year.
- यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 56.7% के स्तर से कम था।
- The improvement in fiscal position was driven by stronger tax revenues and a fiscal surplus recorded in December.
- राजकोषीय स्थिति में यह सुधार मजबूत कर राजस्व और दिसंबर में दर्ज राजकोषीय अधिशेष के कारण हुआ।

- Gross tax revenues rose sharply by 32.3% in December, taking overall growth during April–December to 8.5%.
- दिसंबर में सकल कर राजस्व 32.3% बढ़ा, जिससे अप्रैल–दिसंबर अवधि की कुल वृद्धि 8.5% हो गई।
- Capital expenditure growth slowed during this period, which helped in containing the fiscal deficit.
- इस अवधि में पूंजीगत व्यय की वृद्धि धीमी रही, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- The government has targeted limiting the full-year FY26 fiscal deficit to 4.4% of GDP.
- सरकार ने पूरे FY26 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।

Ques: After the proposed merger of Union Bank of India and Bank of India, what will be the overall ranking of the combined entity in India?

प्रस्तावित विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त इकाई भारत में किस स्थान पर होगी?

- A) Largest bank / सबसे बड़ा बैंक
- B) Second-largest bank / दूसरा सबसे बड़ा बैंक
- C) Third-largest bank / तीसरा सबसे बड़ा बैंक
- D) Fourth-largest bank / चौथा सबसे बड़ा बैंक
- E) Fifth-largest bank / पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The initial merger process between Union Bank of India and Bank of India has begun and may be completed by the end of the calendar year.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विलय की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है।
- The Government of India aims to merge smaller public sector banks with larger ones to reduce the number of PSU banks from 12 to about 4–5.
- भारत सरकार छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर 12 के बजाय

लगभग 4-5 बड़े PSU बैंक बनाना चाहती है।

- The merger would create one of India's largest public sector lenders with an expanded balance sheet, branch network, and customer base.
- यह विलय विस्तारित बैलेंस शीट, शाखा नेटवर्क और ग्राहक आधार के साथ भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में से एक का निर्माण करेगा।
- The combined entity is expected to become the second-largest PSU bank with assets of about ₹25.4 lakh crore in FY25.
- संयुक्त इकाई FY25 में लगभग ₹25.4 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक बन जाएगी।
- Overall, it would be the third-largest bank in India after State Bank of India (SBI) and HDFC Bank.
- कुल मिलाकर, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और HDFC बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।

Ques: Which bank has launched India's first savings account linked to 100% of the RBI Repo rate?

किस बैंक ने भारत का पहला 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा बचत खाता लॉन्च किया है?

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) Slice Small Finance Bank / स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Slice Small Finance Bank (Slice SFB) has introduced three new financial products.
- स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक (Slice SFB) ने तीन नए वित्तीय उत्पाद पेश किए हैं।
- These include a Digital Savings Account linked to the RBI Repo rate, a UPI-integrated credit card, and digital Fixed Deposits (FDs).
- इनमें RBI रेपो रेट से जुड़ा डिजिटल बचत खाता, UPI-इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड और

डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शामिल हैं।

- Slice launched India's first savings account linked to 100% of the Repo rate of the Reserve Bank of India (RBI).
- स्लाइस ने भारत का पहला ऐसा बचत खाता लॉन्च किया है जो 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा है।
- Interest on the savings account is calculated and credited daily, allowing real-time growth of money.
- इस बचत खाते पर ब्याज की गणना और जमा प्रतिदिन की जाती है, जिससे धन वास्तविक समय में बढ़ता है।
- The digital Fixed Deposits offer interest rates of up to 7.25% per annum.
- डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.25% प्रति वर्ष तक ब्याज दिया जाता है।
- These FDs are insured up to ₹5 lakh by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- ये एफडी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा ₹5 लाख तक बीमित हैं।
- The card offers up to 3% cashback based on usage, a "Slice in 3" feature for no-cost Equated Monthly Investment (EMI) conversion on purchases above Rs.2,000, weekly rewards through Slice Sparks.

About Slice Small Finance Bank :

- Established : 2016
- HQ : Guwahati, Assam
- CEO Rajan Bajaj

Ques: The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by which regulatory body?

रीइंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन किस नियामक संस्था द्वारा किया गया है?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
- D) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड

नियामक एवं विकास प्राधिकरण
E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- रीइश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया गया है।
- The committee has been reconstituted for a period of three years.
- समिति का पुनर्गठन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।
- It has been constituted under Section 101B of the Insurance Act, 1938.
- इसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101B के अंतर्गत किया गया है।
- The RAC is chaired by A.V. Girija Kumar, former Chairman and Managing Director (CMD) of Oriental Insurance Company Limited (OICL).
- RAC के अध्यक्ष ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ए.वी. गिरिजा कुमार हैं।
- Aruna Bowrampet, Deputy General Manager (Reinsurance), IRDAI, serves as the Secretary of the committee.
- IRDAI की डिप्टी जनरल मैनेजर (रीइश्योरेंस) अरुणा बोवरामपेट समिति की सचिव हैं।
- The objective of the RAC is to strengthen IRDAI's advisory support on reinsurance-related matters.
- RAC का उद्देश्य रीइश्योरेंस से जुड़े मामलों पर IRDAI की परामर्श सहायता को मजबूत करना है।

About IRDAI :

- ESTD : 1999
- HQ : Hyderabad
- Chairman : Ajay Seth

Ques: Which company recently received the Payment Aggregator–Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI)?

हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है?

- A) Paytm Payments Services / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) Paysharp / पेसशार्प
- D) PhonePe / फोनपे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Paysharp has received the Payment Aggregator-Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI).
- पेसशार्प को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- The licence enables Paysharp to operate as a physical (offline) payment aggregator.
- यह लाइसेंस पेसशार्प को भौतिक (ऑफलाइन) पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
- This approval will help the company enhance its payment service offerings.
- इस स्वीकृति से कंपनी अपनी भुगतान सेवाओं को और सुदृढ़ कर सकेगी।
- Earlier, in August 2024, Paysharp had received the Payment Aggregator-Online (PA-O) licence.
- इससे पहले, अगस्त 2024 में पेसशार्प को पेमेंट एग्रीगेटर-ऑनलाइन (PA-O) लाइसेंस प्राप्त हुआ था।

Ques: State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA for what primary purpose?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA किस मुख्य उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है?

- A) Promoting digital retail banking / डिजिटल रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देना
- B) Financing MSMEs only / केवल एमएसएमई को वित्तपोषण

- C) Financing sunrise sectors critical to India's economic transformation / भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों का वित्तपोषण
- D) Strengthening agricultural credit / कृषि ऋण को मजबूत करना
- E) Expanding overseas banking operations / विदेशी बैंकिंग परिचालन का विस्तार

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA, a Centre of Excellence (CoE).
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) लॉन्च किया है।
- CHAKRA aims to finance sunrise sectors that are critical to India's economic transformation.
- CHAKRA का उद्देश्य भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषित करना है।
- The combined potential investment in these sunrise sectors is estimated at around ₹100 trillion over the next five years.
- इन उभरते क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹100 ट्रिलियन के संभावित निवेश का अनुमान है।
- SBI has estimated a lendable opportunity of about ₹20–22 trillion in these sectors during the same period.
- SBI ने इन क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹20–22 ट्रिलियन के ऋण अवसर का अनुमान लगाया है।
- SBI has signed Memoranda of Understanding (MoUs) with 21 financial institutions.
- SBI ने 21 वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Under these MoUs, project finance teams of partner institutions will work alongside the SBI team at CHAKRA.
- इन समझौतों के तहत साझेदार संस्थानों की परियोजना वित्त टीम CHAKRA में तैनात SBI टीम के साथ कार्य करेगी।
- This collaboration will enable capacity building and co-financing of projects.
- इस सहयोग से क्षमता निर्माण और परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण संभव होगा।

Ques: In which month did UPI record its highest-ever transaction volume of about 21.6 billion?

UPI ने लगभग 21.6 अरब का अब तक का सबसे अधिक लेन-देन किस महीने में दर्ज किया?

- A) October 2025 / अक्टूबर 2025
- B) November 2025 / नवंबर 2025
- C) August 2025 / अगस्त 2025
- D) September 2025 / सितंबर 2025
- E) December 2025 / दिसंबर 2025

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- UPI transaction volume reached a record 21.6 billion in December 2025, the highest ever recorded.
- दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन की संख्या 21.6 अरब तक पहुँच गई, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
- This surpassed the previous record of 20.47 billion transactions in November 2025.
- इसने नवंबर 2025 के 20.47 अरब लेन-देन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- The total value of UPI transactions in December 2025 rose to around ₹28 lakh crore.
- दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन का कुल मूल्य लगभग ₹28 लाख करोड़ रहा।
- This value exceeded the earlier peak of about ₹27.3 lakh crore recorded in October 2025.
- यह अक्टूबर 2025 में दर्ज ₹27.3 लाख करोड़ के पिछले उच्चतम स्तर से भी अधिक था।
- The growth reflects increased digital payment adoption, festive spending, and expansion of the UPI ecosystem.
- यह वृद्धि डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने, त्योहारी खर्च और UPI इकोसिस्टम के विस्तार को दर्शाती है।

Ques: Who holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India?

भारत में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है?

- A) Manmohan Singh / मनमोहन सिंह
- B) Yashwant Sinha / यशवंत सिन्हा
- C) Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- D) Morarji Desai / मोरारजी देसाई
- E) P. Chidambaram / पी. चिदंबरम

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Finance Minister Nirmala Sitharaman is set to present her 9th consecutive Union Budget since assuming office in 2019.
 - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 से अब तक लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।
 - She has already presented eight consecutive Union Budgets, the longest continuous run by any Finance Minister in India.
 - उन्होंने अब तक लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जो किसी भी भारतीय वित्त मंत्री द्वारा सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला है।
 - With the ninth Budget, she moves closer to the all-time record held by Morarji Desai.
 - 9वें बजट के साथ वह मोरारजी देसाई के सर्वकालिक रिकॉर्ड के और करीब पहुँच जाएंगी।
 - Former Prime Minister Morarji Desai holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India — a total of 10.
 - पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल 10 केंद्रीय बजट पेश किए थे, जो अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।
-

Ques: Under the revised Liberalised Remittance Scheme (LRS) rules, what is the new TCS rate on education and medical remittances above ₹10 lakh?
संशोधित लिबरलाइज्ड रेमिटेस स्कीम (LRS) नियमों के तहत ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेस पर नया TCS दर क्या है?

- A) 1%

- B) 2%
- C) 5%
- D) 10%
- E) 20%

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Union Budget rationalised Tax Collected at Source (TCS) on outward remittances under RBI's Liberalised Remittance Scheme (LRS).
- केंद्रीय बजट ने RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी रेमिटेंस पर TCS को तर्कसंगत बनाया।
- TCS on education and medical remittances above ₹10 lakh has been reduced from 5% to 2%.
- ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेंस पर TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
- The reduction will ease liquidity pressure and ensure more funds directly reach students and patients abroad.
- इस कमी से नकदी दबाव कम होगा और छात्रों व मरीजों तक अधिक धन सीधे पहुंचेगा।
- Lower TCS will reduce cash blockage at the point of remittance.
- कम TCS से रेमिटेंस के समय धन अटकने की समस्या घटेगी।
- TCS on overseas tour packages has also been rationalised to a flat 2%.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS को भी फ्लैट 2% कर दिया गया है।
- Earlier, overseas tour remittances attracted 5% TCS below ₹10 lakh and 20% above ₹10 lakh.
- पहले विदेशी टूर रेमिटेंस पर ₹10 लाख से कम पर 5% और ₹10 लाख से अधिक पर 20% TCS लगता था।
- In November 2025, total outward remittances under LRS stood at \$1,937 million, showing a decline from October.
- नवंबर 2025 में LRS के तहत कुल विदेशी रेमिटेंस \$1,937 मिलियन रहा, जो अक्टूबर की तुलना में कम है।

Ques: Under Union Budget 2026–27, what is the revised Tax Collected at Source (TCS) rate on overseas tour packages?

केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत विदेशी टूर पैकेज पर संशोधित स्रोत पर कर संग्रह (TCS) दर क्या है?

- A) 5%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 2%
- E) 1%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Under the Union Budget 2026-27, interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) to a natural person has been exempted from income tax.
- केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को दिया गया ब्याज आयकर से मुक्त कर दिया गया है।
- The TCS rate on overseas tour packages has been reduced from 5% 20% to 2% without any minimum amount threshold.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS दर को 5% 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, बिना किसी राशि सीमा के।
- Under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), the TCS rate for education and medical purposes has also been reduced from 5% to 2%.
- उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- The time limit for revising income tax returns has been extended from 31 December to 31 March with a nominal fee.
- आयकर रिटर्न संशोधन की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, मामूली शुल्क के साथ।
- ITR-1 and ITR-2 filers can continue filing returns till 31 July, while non-audit business cases and trusts are allowed time till 31 August.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक, जबकि नॉन-ऑडिट व्यवसाय मामलों और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
- These measures aim to simplify compliance and enhance ease of living for taxpayers.
- इन उपायों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन

सुगमता बढ़ाना है।

Ques: In which city did the State Bank of India launch a Global Trade Finance Centre (GTFC) to strengthen its trade finance and global banking operations? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर (GTFC) किस शहर में शुरू किया?

- A) Kolkata / कोलकाता
- B) New Delhi / नई दिल्ली
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Mumbai / मुंबई
- E) Bengaluru / बेंगलुरु

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India, India's largest Public Sector Bank, launched a Global Trade Finance Centre to strengthen its trade finance and global banking operations.
- भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर शुरू किया।
- The GTFC was launched in Kolkata.
- यह GTFC कोलकाता में शुरू किया गया।
- In July 2025, SBI launched two specialized GTFCs in Kolkata and Hyderabad, Telangana, on the occasion of its 70th anniversary.
- जुलाई 2025 में, एसबीआई ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता और तेलंगाना के हैदराबाद में दो विशेष GTFC शुरू किए।
- The GTFC uses advanced technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, and Blockchain.
- GTFC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- The initiative marks a shift from traditional paper-based trade finance systems to digital processes.
- यह पहल पारंपरिक कागज़-आधारित व्यापार वित्त प्रणालियों से डिजिटल प्रक्रियाओं

की ओर बदलाव को दर्शाती है।

Ques: What was the total value of UPI transactions in January, as per NPCI data?

NPCI के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना था?

- A) ₹27.97 lakh crore
- B) ₹25.40 lakh crore
- C) ₹28.33 lakh crore
- D) ₹30.10 lakh crore
- E) ₹21.75 lakh crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- As per data released by the National Payments Corporation of India (NPCI), UPI transaction value touched a record high of ₹28.33 lakh crore in January.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का मूल्य ₹28.33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- The total number of UPI transactions in January stood at 2,170 crore.
- जनवरी में कुल UPI लेनदेन 2,170 करोड़ दर्ज किए गए।
- In December, the UPI transaction value was ₹27.97 lakh crore, showing a sharp rise in January.
- दिसंबर में UPI लेनदेन का मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ था, जो जनवरी में बढ़ गया।
- Month-on-month growth in UPI transaction value was recorded at 21%.
- मूल्य के आधार पर UPI लेनदेन में महीने-दर-महीने 21% की वृद्धि हुई।
- Average daily UPI transactions during January were around 70 crore.
- जनवरी में औसतन प्रतिदिन लगभग 70 करोड़ UPI लेनदेन हुए।
- The average daily transaction value stood at about ₹91,400 crore.
- औसत दैनिक लेनदेन मूल्य लगभग ₹91,400 करोड़ रहा।
- In January 2026, UPI transactions recorded a year-on-year growth of 28% in value terms.
- जनवरी 2026 में UPI लेनदेन मूल्य में 28% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- NPCI noted that the growth momentum of UPI continues to strengthen with increasing adoption of digital payments.

- NPCI के अनुसार डिजिटल भुगतान को अपनाने के साथ UPI की विकास गति लगातार मजबूत हो रही है।

Ques: What is the annual financing commitment under the new Country Partnership Framework (CPF) announced by the Government of India and the World Bank Group?

भारत सरकार और विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) के तहत वार्षिक वित्तपोषण प्रतिबद्धता कितनी है?

- A) USD 3–5 billion
- B) USD 5–7 billion
- C) USD 6–8 billion
- D) USD 10–12 billion
- E) USD 8–10 billion

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India and the World Bank Group announced a new Country Partnership Framework to accelerate job creation in both urban and rural areas.
- भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को तेज करने के लिए नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क घोषित किया।
- The framework includes an annual financing commitment of USD 8–10 billion for the next five years.
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों के लिए USD 8–10 बिलियन का वार्षिक वित्तपोषण प्रस्तावित है।
- The new CPF came into effect from the beginning of January 2026.
- यह नया CPF जनवरी 2026 की शुरुआत से प्रभावी हुआ।
- The framework aligns with India's "Viksit Bharat" vision of becoming a developed nation by 2047.
- यह फ्रेमवर्क भारत के "विकसित भारत" विज़न के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।
- The World Bank was established in 1944 and is headquartered in Washington D.C.

- विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है।
 - The World Bank has 189 member countries.
 - विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं।
-

**Ques: From which date will the Income Tax Act, 2025 come into effect?
आयकर अधिनियम, 2025 किस तिथि से लागू होगा?**

- A) 1st January 2026
- B) 1st April 2025
- C) 1st April 2026
- D) 1st July 2026
- E) 31st March 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Income Tax Act, 2025 will come into force from 1st April 2026.
- आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
- The Finance Minister announced that simplified Income Tax Rules and Forms will be notified soon.
- वित्त मंत्री ने बताया कि सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे।
- Tax forms have been redesigned to make compliance easier for common taxpayers.
- आम करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने हेतु आयकर फॉर्म को पुनः डिज़ाइन किया गया है।
- The timeline for filing Income Tax Returns has been extended.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।
- ITR-1 and ITR-2 filers can file returns till 31st July.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- Non-audit business cases and trusts will be allowed to file returns till 31st August.
- नॉन-ऑडिट बिजनेस मामलों और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की

अनुमति होगी।

- The fiscal deficit for FY 2026–27 is estimated at 4.3% of GDP, lower than 4.4% in the current fiscal year.
- वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% अनुमानित है, जो वर्तमान वित्त वर्ष के 4.4% से कम है।
- No deduction will be allowed on interest expenditure related to dividend income or mutual fund income.
- डिविडेंड आय या म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज व्यय पर कोई कटौती अनुमत्य नहीं होगी।
- These provisions aim to improve ease of compliance and enhance ease of living for taxpayers.
- इन प्रावधानों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन सुगमता बढ़ाना है।

Ques: Up to what level is the Government of India considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs)?

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में FDI सीमा कितनी करने पर विचार कर रही है?

- A) 26%
- B) 40%
- C) 49%
- D) 51%
- E) 74%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Union Government is considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs) from 20% to 49%.
- केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में FDI सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है।
- The proposal aims to strengthen the capital base of state-run banks and make them more competitive with private sector banks.

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बैंकों की पूंजी स्थिति को मजबूत करना और उन्हें निजी बैंकों के बराबर लाना है।
- Inter-ministerial consultations are currently underway regarding this proposal.
- इस प्रस्ताव को लेकर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है।
- The move was confirmed by Financial Services Secretary M. Nagaraju.
- इस कदम की पुष्टि वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने की है।
- At present, private banks are allowed up to 49% FDI, while PSBs remain capped at 20%.
- वर्तमान में निजी बैंकों में 49% तक FDI की अनुमति है, जबकि PSBs में सीमा 20% है।
- Higher FDI can help PSBs raise capital, expand lending capacity, and manage larger risks.
- अधिक FDI से PSBs को पूंजी जुटाने, ऋण विस्तार करने और बड़े जोखिम संभालने में मदद मिलेगी।
- The government believes India needs 3–4 globally large banks; currently, only SBI and HDFC Bank figure among the world's top lenders.
- सरकार का मानना है कि भारत को 3–4 वैश्विक स्तर के बड़े बैंक चाहिए, जबकि फिलहाल केवल SBI और HDFC Bank ही शीर्ष वैश्विक बैंकों में शामिल हैं।

Ques : Which bank has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited to offer its Mutual Fund products to customers?

किस बैंक ने अपने ग्राहकों को HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण समझौता किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- Central Bank of India (CBI) has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौता किया है।
- Under this partnership, CBI will offer HSBC AMC's Mutual Fund products to its customers.
- इस साझेदारी के तहत CBI अपने ग्राहकों को HSBC AMC के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराएगा।
- The offerings include equity, debt, and hybrid mutual fund schemes.
- इन पेशकशों में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजनाएँ शामिल हैं।
- These mutual fund products will be accessible through CBI's branches as well as its digital platforms.
- ये म्यूचुअल फंड उत्पाद CBI की शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

About Central Bank of India :

- Established : 1911
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Kalyan Kumar
- Tagline : Central to you since 1911

Ques: Who has been approved by RBI as the Managing Director (MD) & CEO of YES Bank?

RBI ने YES बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी है?

- A) Prashant Kumar / प्रशांत कुमार
- B) Ravneet Gill / रवनीत गिल
- C) Vinay Muralidhar Tonse / विनय मुरलीधर टोंसे
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Amitabh Chaudhry / अमिताभ चौधरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved the appointment of Vinay Muralidhar Tonse as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of YES Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनय मुरलीधर टोंसे को YES बैंक का प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
- The appointment has been approved for a term of three years.
- यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है।
- YES Bank is a private sector bank with its headquarters in Mumbai.
- YES बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- As per banking regulations, RBI approval is mandatory for the appointment of MD & CEO of banks.
- बैंकिंग नियमों के तहत MD और CEO की नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी अनिवार्य होती है।
- The approval highlights RBI's supervisory role in ensuring fit and proper management of banks.
- यह मंजूरी बैंकों में उपयुक्त और सक्षम प्रबंधन सुनिश्चित करने में RBI की पर्यवेक्षी भूमिका को दर्शाती है।

Ques : Which country's central bank approved the first USD-backed stablecoin named USDU?

किस देश के केंद्रीय बैंक ने USDU नामक पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है?

- A) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
- B) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
- C) United Arab Emirates / संयुक्त अरब अमीरात
- D) Singapore / सिंगापुर
- E) Switzerland / स्विट्ज़रलैंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Central Bank of the United Arab Emirates (UAE) has approved the

country's first USD-backed stablecoin.

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने देश के पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है।
- The stablecoin is named USDU.
- इस स्टेबलकॉइन का नाम USDU है।
- USDU has been approved under the Payment Token Services Regulation framework of the UAE Central Bank.
- USDU को UAE केंद्रीय बैंक के पेमेंट टोकन सर्विसेज़ रेगुलेशन फ्रेमवर्क के तहत स्वीकृति दी गई है।
- The approval marks a significant step toward regulating digital assets and payment tokens in the UAE.
- यह मंजूरी UAE में डिजिटल एसेट्स और पेमेंट टोकन के विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- USDU is issued and managed by Universal Digital Intl Limited.
- USDU को यूनिवर्सल डिजिटल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है।

Ques: Which global investment firm received RBI approval to acquire up to 9.99% stake in Federal Bank?

किस वैश्विक निवेश कंपनी को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?

- A) Brookfield / ब्रुकफील्ड
- B) KKR / केकेआर
- C) Blackstone / ब्लैकस्टोन
- D) Carlyle / कार्लाइल
- E) Warburg Pincus / वारबर्ग पिंगस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved Blackstone's acquisition of up to 9.99% stake in Federal Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है।
- With this approval, Blackstone will become the largest shareholder of Federal Bank.
- इस मंजूरी के बाद ब्लैकस्टोन फेडरल बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा।
- The total investment value of the deal is approximately ₹6,196 crore.
- इस सौदे का कुल निवेश मूल्य लगभग ₹6,196 करोड़ है।
- The acquisition has been approved under RBI norms governing Foreign Portfolio Investors (FPIs) in private sector banks.
- यह अधिग्रहण निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से संबंधित RBI के नियमों के तहत स्वीकृत किया गया है।
- The deal highlights the growing interest of foreign investors in India's private banking sector.
- यह सौदा भारत के निजी बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

Ques: Which Regional Rural Bank (RRB) became the first in India to launch a co-branded RuPay credit card?

भारत में सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) कौन सा है?

- A) Assam Gramin Vikash Bank / असम ग्रामीण विकास बैंक
- B) Kerala Gramin Bank / केरल ग्रामीण बैंक
- C) Karnataka Gramin Bank / कर्नाटक ग्रामीण बैंक
- D) Bihar Gramin Bank / बिहार ग्रामीण बैंक
- E) Tripura Gramin Bank / त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या :

- Tripura Gramin Bank (TGB), in collaboration with its sponsor bank Punjab National Bank (PNB), launched a co-branded RuPay credit card.
- त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (TGB) ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के सहयोग से सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- With this initiative, TGB became the first Regional Rural Bank (RRB) in India to introduce a co-branded RuPay credit card.
- इस पहल के साथ TGB भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) बन गया जिसने सह-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड पेश किया।
- It is also the first among the eight RRBs sponsored by PNB to achieve this milestone.
- यह PNB द्वारा प्रायोजित आठ RRBs में भी ऐसा करने वाला पहला बैंक है।
- The launch was held at Agartala, Tripura, marking the Golden Jubilee (50 years) of Tripura Gramin Bank.
- यह लॉन्च त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) का प्रतीक है।

Ques: What decision did the RBI's Monetary Policy Committee (MPC) take regarding the repo rate in its latest policy review?

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नवीनतम नीति समीक्षा में रेपो रेट पर क्या निर्णय लिया?

- A) Reduced to 5.00% / 5.00% कर दिया
- B) Increased to 5.50% / 5.50% कर दिया
- C) Kept unchanged at 5.25% / 5.25% पर स्थिर रखा
- D) Reduced to 4.75% / 4.75% कर दिया
- E) Increased to 6.00% / 6.00% कर दिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) unanimously decided to keep the repo rate unchanged at 5.25%, continuing the pause on interest rates.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया और ब्याज दरों पर विराम जारी रखा।
- The decision was taken by the Monetary Policy Committee (MPC) amid improving economic growth prospects.
- यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा बेहतर होते आर्थिक परिदृश्य के बीच लिया गया।
- The MPC revised India's GDP growth projection for FY2025–26 to 7.4%, up from the earlier estimate of 7.3%.
- MPC ने FY2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- The policy stance reflects confidence in India's economic momentum following a strong policy and reform-driven week.
- यह नीतिगत रुख मजबूत आर्थिक गति और हालिया नीतिगत फैसलों पर RBI के भरोसे को दर्शाता है।
- Stable inflation conditions and robust growth outlook supported the decision to maintain the status quo on rates.
- नियंत्रित महंगाई और मजबूत विकास अनुमान के कारण ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

Ques : Under the new Risk-Based Premium (RBP) framework, which category of banks will pay the lowest deposit insurance premium?

नए जोखिम-आधारित प्रीमियम (RBP) ढांचे के तहत कौन-सी श्रेणी के बैंक सबसे कम जमा बीमा प्रीमियम देंगे?

- A) Category A / श्रेणी A
- B) Category B / श्रेणी B
- C) Category C / श्रेणी C
- D) Category D / श्रेणी D
- E) All will pay the same / सभी समान भुगतान करेंगे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या

- From 1 April 2026, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), a subsidiary of RBI, will implement a Risk-Based Premium (RBP) framework.
- 1 अप्रैल 2026 से, RBI की सहायक संस्था DICGC जोखिम-आधारित प्रीमियम (RBP) ढांचा लागू करेगी।
- Under this system, banks will pay 8–12 paise per ₹100 deposit per year, depending on their risk category.
- इस प्रणाली के तहत बैंक ₹100 जमा पर 8 से 12 पैसे प्रति वर्ष प्रीमियम देंगे।
- Category-wise Premium Structure | श्रेणी-वार प्रीमियम संरचना:
 - Category A (Lowest Risk): 8 paise
 - Category B: 10 paise
 - Category C: 11 paise
 - Category D (Highest Risk): 12 paise
- Currently, DICGC charges a flat premium of 12 paise per ₹100 deposit to all banks.
- वर्तमान में DICGC सभी बैंकों से ₹100 जमा पर 12 पैसे का समान प्रीमियम वसूलता है।
- The DICGC Act, 1961 allows differential premium rates for banks based on risk.
- DICGC अधिनियम, 1961 जोखिम के आधार पर अलग-अलग प्रीमियम दरों की अनुमति देता है।
- Banks will be classified into A, B, C and D categories based on DICGC's internal risk assessment.
- बैंकों को DICGC की आंतरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर A, B, C और D श्रेणियों में रखा जाएगा।

Ques: Which organisation approved USD 830 million for India's PM-SETU

programme?

भारत के PM-SETU कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस संगठन ने स्वीकृत किए हैं?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- D) New Development Bank (NDB) / नया विकास बैंक
- E) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या :

- The World Bank approved USD 830 million for India's Pradhan Mantri – Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) programme.
- विश्व बैंक ने भारत के PM-SETU (उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार परिवर्तन) कार्यक्रम के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए।
- The funding aims to upgrade Industrial Training Institutes (ITIs) and improve skilling and employability outcomes across India.
- इस वित्तपोषण का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन कर कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
- The loan is part of the World Bank Group's Country Partnership Framework (CPF) for India (FY 2026–31).
- यह ऋण भारत के लिए विश्व बैंक समूह की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (वित्त वर्ष 2026–31) का हिस्सा है।
- Under the CPF, the World Bank Group envisages USD 8–10 billion in annual financing for India.
- इस फ्रेमवर्क के तहत भारत को प्रति वर्ष 8–10 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है।
- The loan has a tenure of 19.5 years, including a 4-year grace period.
- इस ऋण की अवधि 19.5 वर्ष है, जिसमें 4 वर्ष की मोहलत अवधि (Grace Period)

शामिल है।

Ques: What disinvestment and asset monetisation target has the Centre set for FY27 under the Union Budget 2026?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 के तहत FY27 के लिए विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

- A) ₹34,000 crore
- B) ₹47,000 crore
- C) ₹60,000 crore
- D) ₹75,000 crore
- E) ₹80,000 crore

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या :

- The Centre has set an ambitious target of ₹80,000 crore from disinvestment and asset monetisation for FY27, indicating a renewed push to strengthen non-tax revenues under Union Budget 2026.
- केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 के तहत FY27 के लिए विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से ₹80,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे गैर-कर राजस्व को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- The ₹80,000 crore target has been budgeted under Miscellaneous Capital Receipts for 2026–27.
- ₹80,000 करोड़ का लक्ष्य 2026–27 के लिए विविध पूंजीगत प्राप्तियों (Miscellaneous Capital Receipts) के अंतर्गत रखा गया है।
- This marks a sharp increase from the revised estimate of about ₹34,000 crore for the current financial year.
- यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान ₹34,000 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है।
- For FY26, the government had originally budgeted ₹47,000 crore, but weak execution led to a downward revision.
- FY26 में सरकार ने शुरू में ₹47,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन कमजोर

कार्यान्वयन के कारण इसमें कटौती करनी पड़ी।

- Actual receipts in FY25 stood at just ₹20,214 crore, highlighting persistent challenges in achieving disinvestment targets.
- FY25 में वास्तविक प्राप्तियां केवल ₹20,214 करोड़ रहीं, जो विनिवेश लक्ष्यों को हासिल करने में लगातार आ रही चुनौतियों को दर्शाता है।

Ques: RBI has increased the collateral-free loan limit for Micro and Small Enterprises (MSEs) to how much?

RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा कितनी कर दी है?

- A) ₹10 lakh
- B) ₹15 lakh
- C) ₹20 lakh
- D) ₹25 lakh
- E) ₹50 lakh

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has doubled the collateral-free loan limit for Micro and Small Enterprises (MSEs) from ₹10 lakh to ₹20 lakh.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी है।
- The enhanced limit will apply to all loans sanctioned or renewed on or after April 1.
- बढ़ी हुई ऋण सीमा 1 अप्रैल या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।
- The move aims to improve access to credit for MSEs and support their growth.
- इस कदम का उद्देश्य MSEs को आसान ऋण उपलब्ध कराना और उनके विकास को

समर्थन देना है।

- Collateral-free loans reduce dependence on asset-backed lending, especially for small businesses.
- बिना गारंटी ऋण छोटे व्यवसायों की संपत्ति-आधारित ऋण पर निर्भरता को कम करते हैं।
- The decision is part of RBI's broader strategy to strengthen MSME financing in India.
- यह निर्णय भारत में MSME वित्तपोषण को मजबूत करने की RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

Ques: The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has revised the base year of the Consumer Price Index (CPI) to which year, introducing major changes in item weights and coverage?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष बदलकर किस वर्ष का किया है, जिसमें वस्तुओं के भार और कवरेज में बड़े बदलाव किए गए हैं?

- A) 2015
- B) 2018
- C) 2020
- D) 2022
- E) 2024

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has revised the CPI base year from 2011–12 to 2024.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने CPI का आधार वर्ष 2011–12 से बदलकर 2024 कर दिया है।
- The revised CPI series is named CPI 2024.

- संशोधित CPI श्रृंखला का नाम CPI 2024 रखा गया है।
- The weight of Food & Beverages has been reduced significantly from 45.86% to 36.75%.
- खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है।
- The weight of Housing has increased sharply from 10.07% to 17.66%, due to improved rent measurement methods, which may push housing inflation upward.
- आवास का भार 10.07% से बढ़ाकर 17.66% कर दिया गया है, बेहतर किराया मापन पद्धति के कारण इससे आवास मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
- The revised CPI basket now includes 358 items, up from 299 earlier.
- संशोधित CPI टोकरी में अब 358 वस्तुएँ शामिल हैं, जो पहले 299 थीं।
- Education has been introduced as a standalone category in the reclassified CPI groups.
- शिक्षा को पुनर्वर्गीकृत CPI श्रेणियों में एक स्वतंत्र समूह के रूप में शामिल किया गया है।
- Price data will be collected from 1,465 rural markets and 1,395 urban markets across 434 towns.
- मूल्य आँकड़े 434 नगरों में 1,465 ग्रामीण बाजारों और 1,395 शहरी बाजारों से एकत्र किए जाएंगे।
- Additionally, 12 online markets in cities with a population exceeding 2.5 million will be included to capture weekly prices from e-commerce platforms.
- इसके अतिरिक्त, 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 12 ऑनलाइन बाजारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से साप्ताहिक मूल्य एकत्र करने के लिए जोड़ा जाएगा।
- CPI 2024 adopts the COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose) framework to enhance international comparability.
- CPI 2024 अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मकता बढ़ाने के लिए COICOP 2018 ढांचे को अपनाता है।

Ques: What is the maximum one-time compensation proposed by RBI for victims of digital fraud?

डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए RBI द्वारा प्रस्तावित अधिकतम एकमुश्त मुआवजा कितना है?

- A) ₹10,000
- B) ₹15,000
- C) ₹20,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed a one-time compensation for bank customers affected by digital frauds.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल धोखाधड़ी से प्रभावित बैंक ग्राहकों के लिए एकमुश्त मुआवजे का प्रस्ताव रखा है।
- The maximum compensation amount is ₹25,000 per customer.
- प्रति ग्राहक अधिकतम ₹25,000 तक मुआवजा दिया जाएगा।
- The compensation will be provided from RBI's Depositor Education and Awareness (DEA) Fund.
- यह मुआवजा RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड से दिया जाएगा।
- The scheme will apply to small-value digital fraudulent transactions only.
- यह योजना केवल कम राशि वाले डिजिटल धोखाधड़ी लेनदेन पर लागू होगी।
- The compensation facility will be provided only once per customer.
- यह सुविधा प्रति ग्राहक केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
- The objective of the scheme is to create awareness so that customers do not fall prey to online frauds again.
- इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे दोबारा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार न हों।
- The announcement was made by RBI Governor Sanjay Malhotra.
- इस योजना की घोषणा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई।

Ques: Which bank launched the “Rooftop Solar Finance” product to support MSMEs in adopting solar energy systems?

MSMEs को सोलर ऊर्जा प्रणाली अपनाने में सहायता के लिए “रूफटॉप सोलर फाइनेंस”

उत्पाद किस बैंक ने लॉन्च किया?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank launched “Rooftop Solar Finance”, a dedicated financing product to help Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) adopt solar energy systems on commercial rooftops.
- एक्सिस बैंक ने “रूफटॉप सोलर फाइनेंस” नामक नया वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य MSMEs को व्यावसायिक छतों पर सोलर ऊर्जा प्रणाली अपनाने में सहायता करना है।
- Under this product, MSMEs can avail loans ranging from ₹10 lakh to ₹2 crore without any collateral requirement.
- इस योजना के तहत MSMEs ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का ऋण बिना किसी जमानत के प्राप्त कर सकते हैं।
- The financing facility is available through Axis Bank’s branch network across India.
- यह वित्तीय सुविधा एक्सिस बैंक की देशभर की शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
- The repayment tenure ranges between 4 to 7 years, enabling businesses to align repayments with their cash flows.
- 4 से 7 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि व्यवसायों को कैश फ्लो के अनुसार भुगतान प्रबंधन में मदद करती है।
- The initiative supports clean energy adoption, cost reduction, and sustainability among MSMEs.
- यह पहल स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, लागत में कमी और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को बढ़ावा देती है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: Which institution is planning to issue revised guidelines for the Kisan Credit Card (KCC) scheme?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश कौन-सा संस्थान जारी करने वाला है?

- A) Ministry of Agriculture / कृषि मंत्रालय
- B) NABARD / नाबार्ड
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) is set to issue revised guidelines for banks under the Kisan Credit Card (KCC) scheme.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने वाला है।
- The objective is to boost the farm sector by expanding coverage and streamlining KCC operations.
- इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, कवरेज बढ़ाना और संचालन को सरल बनाना

है।

- Proposed changes include standardisation of crop seasons and extension of KCC tenure up to six years.
- प्रस्तावित बदलावों में फसल मौसम का मानकीकरण और KCC अवधि को छह वर्ष तक बढ़ाना शामिल है।
- Drawing limits will be aligned with the scale of finance for each crop season.
- ड्रॉइंग लिमिट को प्रत्येक फसल मौसम के वित्त पैमाने से जोड़ा जाएगा।
- Expenses on technological interventions may also be included under KCC.
- तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े खर्च भी KCC के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं।
- RBI Governor Sanjay Malhotra stated that draft guidelines will be issued shortly, following a comprehensive review of the scheme.
- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि योजना की व्यापक समीक्षा के बाद मसौदा दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे।
- As per SBI, collateral is waived up to ₹2 lakh, and up to ₹3 lakh under tie-up arrangements.
- SBI के अनुसार ₹2 लाख तक बिना जमानत, और टाई-अप व्यवस्था में ₹3 लाख तक ऋण उपलब्ध है।
- A 3% interest subvention is available on timely repayment for loans up to ₹3 lakh.
- समय पर भुगतान पर ₹3 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है।

Ques: Which district became the first in India to achieve 100% insurance coverage under the “Insurance for All by 2047” initiative?

“इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047” पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना?

- A) Jaipur (Rajasthan) / जयपुर
- B) Alwar (Rajasthan) / अलवर
- C) Indore (Madhya Pradesh) / इंदौर
- D) Surat (Gujarat) / सूरत
- E) Gurugram (Haryana) / गुरुग्राम

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Alwar district in Rajasthan became the first district in India to achieve 100% insurance coverage under the “Insurance for All by 2047” initiative.
- राजस्थान का अलवर जिला “इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047” पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया।
- The initiative is a joint effort of the Government of India (GoI) and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- यह पहल भारत सरकार (GoI) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की संयुक्त पहल है।
- As part of the drive, 1,367 individuals above the age of 10 years were brought under insurance coverage through door-to-door surveys, ensuring full saturation.
- इस अभियान के तहत घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से 10 वर्ष से अधिक आयु के 1,367 लोगों को बीमा के दायरे में लाया गया, जिससे पूर्ण कवरेज सुनिश्चित हुआ।
- The insurance policies were issued by United India Insurance Company Limited (UIIC).
- ये बीमा पॉलिसियाँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) द्वारा जारी की गईं।
- The achievement supports India’s long-term goal of universal insurance coverage by 2047, marking 100 years of Independence.
- यह उपलब्धि 2047 तक सार्वभौमिक बीमा कवरेज के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य (स्वतंत्रता के 100 वर्ष) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Ques: Which NBFCs have been exempted from mandatory RBI registration as per the latest RBI decision?

RBI के हालिया निर्णय के अनुसार किन NBFCs को अनिवार्य RBI पंजीकरण से छूट दी गई है?

- A) All NBFCs operating in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी NBFCs
- B) NBFCs with assets above ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले NBFCs
- C) NBFCs with assets below ₹1,000 crore and no public funds or customer interface /
₹1,000 करोड़ से कम संपत्ति वाले, बिना सार्वजनिक धन और ग्राहक इंटरफेस वाले NBFCs
- D) Only government-owned NBFCs / केवल सरकारी स्वामित्व वाले NBFCs
- E) Foreign NBFCs operating in India / भारत में कार्यरत विदेशी NBFCs

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has exempted certain NBFCs with assets below ₹1,000 crore from mandatory registration.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ₹1,000 करोड़ से कम संपत्ति वाले कुछ NBFCs को अनिवार्य पंजीकरण से छूट दी है।
- This exemption applies only to NBFCs that do not access public funds and do not have any customer interface.
- यह छूट केवल उन NBFCs पर लागू होगी जिनकी सार्वजनिक धन तक पहुंच नहीं है और जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।
- The move aims to reduce compliance burden on smaller NBFCs while ensuring that systemic financial stability is not compromised.
- इस कदम का उद्देश्य छोटे NBFCs पर अनुपालन बोझ कम करना है, साथ ही वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
- RBI has also proposed to remove the requirement of prior approval for certain NBFCs to open more than 1,000 branches.
- RBI ने कुछ NBFCs के लिए 1,000 से अधिक शाखाएँ खोलने हेतु पूर्व अनुमोदन की शर्त हटाने का प्रस्ताव भी रखा है।
- RBI will continue to monitor liquidity and credit flow in the economy.
- RBI अर्थव्यवस्था में तरलता और ऋण प्रवाह की निगरानी जारी रखेगा।

Ques: What major change has the Reserve Bank of India (RBI) made under the Voluntary Retention Route (VRR) for Foreign Portfolio Investors (FPIs)?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए वॉलंटरी रिटेंशन रूट (VRR) के तहत कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Increased investment cap to ₹5 lakh crore / निवेश सीमा ₹5 लाख करोड़ तक बढ़ाई
- B) Removed the ₹2.5 lakh crore overall investment limit / ₹2.5 लाख करोड़ की कुल निवेश सीमा हटा दी
- C) Restricted VRR only to equity investments / VRR को केवल इक्विटी निवेश तक सीमित किया
- D) Suspended VRR temporarily / VRR को अस्थायी रूप से निलंबित किया
- E) Introduced new tax on FPI debt investments / FPI ऋण निवेश पर नया कर लगाया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has removed the overall investment cap of ₹2.5 lakh crore under the Voluntary Retention Route (VRR) for FPIs.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FPIs के लिए VRR के तहत ₹2.5 लाख करोड़ की कुल निवेश सीमा को हटा दिया है।
- Under the revised framework, VRR investments will now be governed by the existing investment ceilings under the General Route.
- संशोधित ढांचे के तहत अब VRR के माध्यम से निवेश सामान्य मार्ग (General Route) की मौजूदा निवेश सीमाओं के अनुसार नियंत्रित होंगे।
- The move aims to deepen domestic bond markets and improve the stability of capital flows.

- इस कदम का उद्देश्य घरेलू बॉन्ड बाजार को गहराई देना और पूंजी प्रवाह की स्थिरता को बढ़ाना है।
- It provides greater flexibility to foreign investors to deploy long-term funds in Indian debt markets.
- यह विदेशी निवेशकों को भारतीय ऋण बाजार में दीर्घकालिक निवेश के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- The decision comes amid tight global financial conditions and rising government borrowing, to boost FPI participation in the bond market.
- यह निर्णय कड़े वैश्विक वित्तीय हालात और बढ़ती सरकारी उधारी के बीच बॉन्ड बाजार में FPI भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

Ques: By what percentage did State Bank of India's (SBI) net profit rise in Q3FY26?

Q3FY26 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा?

- A) 15%
- B) 18.5%
- C) 21%
- D) 24.5%
- E) 30%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) reported a 24.5% year-on-year increase in standalone net profit to ₹21,028 crore in Q3FY26.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने Q3FY26 में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 24.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹21,028 करोड़ का लाभ कमाया।
- Net Interest Income (NII) rose by 9.04%, while Net Interest Margin (NIM) eased slightly to 3.12% from 3.15% a year ago.
- नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 9.04% की वृद्धि हुई, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM)

मामूली घटकर 3.12% रह गया (पिछले वर्ष 3.15%)।

- Gross advances increased by 15.17% to ₹46.8 lakh crore, and gross deposits rose by 9.02% to ₹57 lakh crore.
- ग्राँस एडवांस 15.17% बढ़कर ₹46.8 लाख करोड़, जबकि ग्राँस डिपॉजिट 9.02% बढ़कर ₹57 लाख करोड़ हो गया।
- Asset quality improved, with Gross NPAs declining 12.3% to ₹73,637 crore and Net NPAs falling 15.74% to ₹18,012 crore.
- एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, जहाँ ग्राँस NPA 12.3% घटकर ₹73,637 करोड़ और नेट NPA 15.74% घटकर ₹18,012 करोड़ रह गया।
- The domestic Credit–Deposit ratio stood at 72.98%, improving by 404 basis points YoY.
- घरेलू क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 72.98% रहा, जो साल-दर-साल 404 बेसिस पॉइंट का सुधार दर्शाता है।
- SBI stated it has adequate capital and liquidity buffers to support future credit growth.
- SBI ने कहा कि भविष्य की क्रेडिट वृद्धि को समर्थन देने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है।

Ques: How much gold did the Reserve Bank of India (RBI) purchase in 2025, and what was the main reason for the sharp decline compared to 2024?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में कितना सोना खरीदा और 2024 की तुलना में इसमें भारी गिरावट का मुख्य कारण क्या था?

- A) 16 tonnes; weak global demand / 16 टन; वैश्विक मांग में कमी
- B) 25 tonnes; low foreign reserves / 25 टन; कम विदेशी मुद्रा भंडार
- C) 73 tonnes; stable gold prices / 73 टन; स्थिर सोने की कीमतें
- D) 40 tonnes; change in RBI policy / 40 टन; आरबीआई नीति में बदलाव
- E) 4 tonnes; very high gold prices / 4 टन; सोने की बहुत अधिक कीमतें

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) purchased only 4 tonnes of gold in 2025, a sharp decline from 73 tonnes in 2024.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में केवल 4 टन सोना खरीदा, जो 2024 के 73 टन की तुलना में काफी कम है।
- The primary reason for the slowdown was very high gold prices.
- इस गिरावट का मुख्य कारण सोने की अत्यधिक ऊँची कीमतें रहीं।
- RBI's quarter-wise gold purchases in 2025 were: 3.4 tonnes (Q1), 0.4 tonnes (Q2), 0.2 tonnes (Q3), and 0 tonnes (Q4).
- 2025 में आरबीआई की तिमाही सोना खरीद इस प्रकार रही: Q1-3.4 टन, Q2-0.4 टन, Q3-0.2 टन, Q4-0 टन।
- In comparison, RBI bought 16 tonnes in 2023 and 77 tonnes in 2021, making 2025 one of the lowest gold purchase years.
- तुलना में, आरबीआई ने 2023 में 16 टन और 2021 में 77 टन सोना खरीदा था, जिससे 2025 सबसे कम खरीद वाले वर्षों में शामिल हो गया।
- According to the World Gold Council (WGC), global central banks purchased 328 tonnes of gold in 2025, slightly lower than 345 tonnes in 2024.
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने 2025 में 328 टन सोना खरीदा, जो 2024 के 345 टन से थोड़ा कम है।
- Poland was the largest gold buyer in 2025 with 102 tonnes, followed by Kazakhstan (57 tonnes) and Azerbaijan (53 tonnes).
- पोलैंड 2025 में 102 टन के साथ सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा, इसके बाद कज़ाखस्तान (57 टन) और अज़रबैजान (53 टन) रहे।

Ques: Mission SAKSHAM, launched by the Reserve Bank of India (RBI), is related to capacity building of which sector?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम किस क्षेत्र की क्षमता निर्माण से संबंधित है?

- A) Commercial Banks / वाणिज्यिक बैंक
- B) Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- C) Urban Cooperative Banks / शहरी सहकारी बैंक
D) NBFCs / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
E) Payment Banks / भुगतान बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Mission SAKSHAM (Sahakari Bank Kshamta Nirman) is an initiative of the Reserve Bank of India (RBI) to strengthen Urban Cooperative Banks (UCBs).
- मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को सशक्त बनाना है।
- The mission focuses on enhancing managerial skills, technical capabilities, and operational resilience of UCBs.
- इस मिशन का उद्देश्य UCBs की प्रबंधकीय क्षमता, तकनीकी दक्षता और परिचालन मजबूती को बढ़ाना है।
- It will function as a sector-wide capacity-building and certification framework.
- यह एक क्षेत्र-व्यापी क्षमता निर्माण एवं प्रमाणन ढांचा होगा।
- Training will be delivered through physical training programmes and a scalable digital learning platform.
- प्रशिक्षण भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा।
- Around 1.4 lakh personnel across various functions in UCBs will be trained under the mission.
- इस मिशन के तहत UCBs के विभिन्न कार्यों से जुड़े लगभग 1.4 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- RBI highlighted that UCBs play a key role in financial inclusion and serving the unbanked population.
- RBI ने बताया कि UCBs वित्तीय समावेशन और बैंकिंग से वंचित वर्गों की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Ques: What is the theme of Financial Literacy Week (FLW) 2026 observed by

the Reserve Bank of India (RBI)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मनाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) 2026 की थीम क्या है?

- A) Digital Banking for All / सभी के लिए डिजिटल बैंकिंग
- B) Safe Payments, Secure Nation / सुरक्षित भुगतान, सुरक्षित राष्ट्र
- C) KYC – Your First Step to Safe Banking / KYC – सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम
- D) Financial Inclusion for Growth / विकास के लिए वित्तीय समावेशन
- E) Cyber Safety Awareness / साइबर सुरक्षा जागरूकता

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) will observe Financial Literacy Week (FLW) 2026 from February 9 to 13, 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 9 से 13 फरवरी 2026 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) 2026 मनाएगा।
- The theme of FLW 2026 is “KYC – Your First Step to Safe Banking”.
- FLW 2026 की थीम है – “KYC – सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम”।
- The initiative aims to educate customers about periodic KYC updates, digital safety, and fraud prevention.
- इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को नियमित KYC अपडेट, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करना है।
- RBI has been conducting Financial Literacy Week every year since 2016.
- RBI वर्ष 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है।
- KYC updation is required periodically based on customer risk category or immediately when personal details change (address, mobile number, name, signature, etc.).
- KYC अपडेट ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार समय-समय पर या व्यक्तिगत विवरण में बदलाव होने पर तुरंत आवश्यक होता है।
- As per RBI norms, re-KYC is mandatory every 2 years for high-risk customers,

8 years for medium-risk customers, and 10 years for low-risk customers, or earlier if required by the bank.

• RBI के अनुसार हाई-रिस्क ग्राहकों के लिए 2 वर्ष, मीडियम-रिस्क के लिए 8 वर्ष और लो-रिस्क ग्राहकों के लिए 10 वर्ष में re-KYC अनिवार्य है, या बैंक के कहने पर पहले भी।

Ques: What are the key recommendations of the 16th Finance Commission for the period 2026–31?

16वें वित्त आयोग (2026–31) की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- A) Reduced states' share to 40% and relaxed fiscal deficit norms
- B) Increased states' share to 45% with higher unconditional cash transfers
- C) Retained states' share at 41% with focus on fiscal discipline and outcome-based spending
- D) Abolished horizontal devolution and replaced it with fixed grants
- E) Removed deficit limits for states to boost welfare spending

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The 16th Finance Commission (FC) has recommended retaining the States' share in the divisible pool of central taxes at 41%, the same as recommended by the 15th Finance Commission.
- 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, जो 15वें वित्त आयोग के समान है।

Tax Devolution | कर हस्तांतरण

- Vertical Devolution: 41% of the Central Government's divisible tax pool will be transferred to States.
- वर्टिकल डिवोल्यूशन: केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों को दिया जाएगा।
- Horizontal Devolution: A formula-based mechanism will decide the inter-se

share of each State from this 41% pool.

- हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन: 41% राशि में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा सूत्र-आधारित व्यवस्था से तय होगा।

Grants Recommendation | अनुदान सिफारिशें

- The 16th FC recommended total grants worth ₹9.47 lakh crore for the five-year period (2026–31).
- 16वें वित्त आयोग ने ₹9.47 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।
- **Grants to Local Bodies:**
 - Total: ₹8 lakh crore
 - ₹4.4 lakh crore for rural local bodies
 - ₹3.6 lakh crore for urban local bodies
- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:
 - कुल: ₹8 लाख करोड़
 - ₹4.4 लाख करोड़ ग्रामीण निकायों के लिए
 - ₹3.6 लाख करोड़ शहरी निकायों के लिए
- Additional grants are earmarked for disaster management.
- आपदा प्रबंधन के लिए भी अनुदान शामिल हैं।

Fiscal Discipline Emphasis | राजकोषीय अनुशासन पर जोर

- Caps State fiscal deficit at 3% of GSDP.
- राज्यों के वित्तीय घाटे को GSDP के 3% तक सीमित किया गया।
- Calls for ending off-budget borrowings and rationalising subsidies.
- ऑफ-बजट उधारी समाप्त करने और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर बल।
- Strong emphasis on outcome-based expenditure and greater transparency in tax transfer data.
- परिणाम-आधारित खर्च और कर हस्तांतरण डेटा में पारदर्शिता पर विशेष जोर।

All About the Finance Commission | वित्त आयोग से संबंधित तथ्य:

- Constituted by: President of India

- गठन: भारत के राष्ट्रपति द्वारा
- Constitutional Basis: Article 280 of the Indian Constitution
- संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280
- Frequency: Every five years
- अवधि: प्रत्येक पाँच वर्ष में
- Total Members: 5 (1 Chairman + 4 Members)
- कुल सदस्य: 5 (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य)

16th Finance Commission Details | 16वां वित्त आयोग:

- Tenure: 1 April 2026 – 31 March 2031
- कार्यकाल: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031
- Chairman: Dr. Arvind Panagariya
- अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया
- Full-time Members : Annie George Mathew – Retired bureaucrat and Manoj Panda – Economist
- पूर्णकालिक सदस्य : Annie George Mathew – सेवानिवृत्त नौकरशाह, मनोज पांडा – अर्थशास्त्री
- Part-time Members : Soumya Kanti Ghosh – Chief Economic Advisor, SBI and T. Rabi Sankar – Deputy Governor, RBI
- अंशकालिक सदस्य : सौम्य कांति घोष – मुख्य आर्थिक सलाहकार, SBI, टी. रबी शंकर – डिप्टी गवर्नर, RBI
- Secretary: Ritvik Ranjanam Pandey
- सचिव: ऋत्विक् रंजनम पांडे

Ques: What is the main objective of rolling out Unified Payments Interface (UPI) in Malaysia?

मलेशिया में यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To promote cryptocurrency transactions / क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को बढ़ावा देना
- B) To enable seamless cross-border digital payments / निर्बाध सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना

- C) To replace Malaysia's banking system / मलेशिया की बैंकिंग प्रणाली को बदलना
D) To introduce a new currency in Malaysia / मलेशिया में नई मुद्रा शुरू करना
E) To establish a joint central bank / संयुक्त केंद्रीय बैंक स्थापित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi announced that UPI will soon be rolled out in Malaysia.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि UPI को जल्द ही मलेशिया में शुरू किया जाएगा।
- The initiative aims to enable seamless cross-border digital payments between India and Malaysia.
- इस पहल का उद्देश्य भारत और मलेशिया के बीच निर्बाध सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना है।
- The rollout is expected to boost business, tourism, and remittance flows between the two countries.
- इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और प्रेषण (रेमिटेंस) को बढ़ावा मिलेगा।
- PM Modi stated that India is globally recognised as a “trusted partner for growth,” reflected in recent trade agreements with the UK, US, and EU.
- पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर “विकास के लिए विश्वसनीय भागीदार” के रूप में देखा जाता है, जो यूके, यूएस और ईयू के साथ व्यापार समझौतों में परिलक्षित होता है।
- He described India–Malaysia relations under the guiding principle of “IMPACT” – India-Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation.
- उन्होंने भारत–मलेशिया संबंधों को “IMPACT” – India-Malaysia Partnership for Advancing Collective Transformation के सिद्धांत के तहत बताया।
- PM Modi emphasized deeper regional cooperation by stating, “India’s success is Malaysia’s success, and it is Asia’s success.”
- पीएम मोदी ने कहा, “भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है, और यह एशिया की सफलता है,” जिससे क्षेत्रीय सहयोग की गहराई उजागर होती है।

Ques: Which bank has become India's first custodian to enable Foreign Portfolio Investor (FPI) registration and account opening through Electronic Signatures?

इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पंजीकरण और खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक कौन सा है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Kotak Mahindra Bank has become India's first custodian to enable FPI registration and account opening through Electronic Signatures.
- कोटक महिंद्रा बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से FPI पंजीकरण और खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक बन गया है।
- The bank completed the entire account-opening and licensing process digitally, without any physical paperwork.
- बैंक ने पूरी खाता खोलने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बिना किसी भौतिक दस्तावेज़ के डिजिटल रूप से पूरा किया।
- This move follows the Securities and Exchange Board of India (SEBI) operationalising a unified digital workflow in January 2026.
- यह पहल सेबी (SEBI) द्वारा जनवरी 2026 में लागू किए गए एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो के बाद की गई है।
- The initiative enhances ease of doing business, reduces processing time, and boosts India's attractiveness for foreign investors.

- यह पहल ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देती है, प्रक्रिया समय को कम करती है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक बनाती है।

About Kotak Mahindra Bank :

- Established : 1986
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Ashok Vaswani
- Tagline : Let's make money simple

Ques: Which Act enabled the implementation of 100% Foreign Direct Investment (FDI) in the insurance sector in India from February 5, 2026?

भारत में बीमा क्षेत्र में 5 फरवरी 2026 से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लागू करने वाला अधिनियम कौन-सा है?

- A) Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 / बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
- B) Insurance Act, 1938 / बीमा अधिनियम, 1938
- C) Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 / सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025
- D) Life Insurance Corporation Act, 1956 / जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
- E) Digital Personal Data Protection Act, 2023 / डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India implemented 100% FDI in the insurance sector on February 5, 2026 through the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025, except Section 25, which deals with common

officers and whole-time officers.

- भारत सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से 5 फरवरी 2026 से बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई लागू किया, जिसमें धारा 25 को अपवाद रखा गया है।
- The Act amends three major laws: Insurance Act, 1938; LIC Act, 1956; and IRDAI Act, 1999.
- यह अधिनियम बीमा अधिनियम, 1938; एलआईसी अधिनियम, 1956; और IRDAI अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है।
- The Chairman, MD, or CEO of an insurance company must be an Indian citizen, and mergers between insurance and non-insurance companies are allowed.
- बीमा कंपनी के चेयरमैन, एमडी या सीईओ का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है तथा बीमा और गैर-बीमा कंपनियों के विलय की अनुमति दी गई है।
- The FDI cap in insurance has increased gradually: 26% (pre-2015) → 49% (2015) → 74% (2021) → 100% (2026).
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा क्रमशः बढ़ाई गई: 26% → 49% → 74% → 100%।
- India's insurance penetration stands at 3.7% of GDP, which is below the global average of 7%.
- भारत की बीमा पैठ जीडीपी का 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से कम है।
- Prior regulatory approval for share transfer has been increased from 1% to 5%, and Net Owned Fund for Foreign Reinsurance Branches has been reduced from ₹5,000 crore to ₹1,000 crore.
- शेयर हस्तांतरण के लिए पूर्व नियामक अनुमोदन सीमा 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फंड ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ किया गया है।
- LIC has been granted autonomy to open Zonal Offices and align foreign offices with local laws.
- एलआईसी को जोनल कार्यालय खोलने की स्वायत्तता दी गई है।
- A Policyholders' Education and Protection Fund will be established, policyholder data must comply with DPDP Act, 2023, and IRDAI has been empowered to disgorge wrongful gains.
- पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की स्थापना होगी, डेटा सुरक्षा DPDP अधिनियम, 2023 के अनुरूप होगी और IRDAI को गलत लाभ की वसूली का अधिकार दिया गया है।

Ques: Why were six Regional Rural Banks (RRBs) altered in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में छह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में परिवर्तन क्यों किया गया?

- A) Due to privatization of Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के कारण
- B) Due to implementation of Basel III norms / बेसल-III मानदंडों के कार्यान्वयन के कारण
- C) As part of the Government's "One State, One RRB" consolidation drive / सरकार की "वन स्टेट, वन RRB" समेकन नीति के तहत
- D) Due to merger of RRBs with cooperative banks / आरआरबी के सहकारी बैंकों में विलय के कारण
- E) Due to non-compliance with RBI capital norms / आरबीआई पूंजी मानदंडों का पालन न करने के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Six Regional Rural Banks (RRBs) have been altered in the Second Schedule of the RBI Act, 1934 as part of the Government's "One State, One RRB" consolidation drive (Phase-4).
- सरकार की "वन स्टेट, वन आरआरबी" समेकन योजना (चरण-4) के तहत छह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिवर्तन किया गया है।
- This consolidation reduced the total number of RRBs from 43 to 28, effective May 1, 2025.
- इस प्रक्रिया से 1 मई 2025 से आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई।
- As a result of mergers, the names of six RRBs were changed and officially updated in the Second Schedule:

- Assam Gramin Vikash Bank → Assam Gramin Bank
 - Chhattisgarh Rajya Gramin Bank → Chhattisgarh Gramin Bank
 - Jharkhand Rajya Gramin Bank → Jharkhand Gramin Bank
 - Kerala Gramin Bank → Kerala Grameena Bank
 - Puduvai Bharathiyar Grama Bank → Puducherry Grama Bank
 - Sarva Haryana Gramin Bank → Haryana Gramin Bank
- The Second Schedule of the RBI Act, 1934 lists all Scheduled Banks in India.
 - RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में भारत के सभी अनुसूचित बैंक सूचीबद्ध होते हैं।
 - Section 2(e) defines a Scheduled Bank, while Section 42(6)(b) empowers RBI to alter or exclude bank names due to mergers or restructuring.
 - धारा 2(e) अनुसूचित बैंक को परिभाषित करती है और धारा 42(6)(b) आरबीआई को विलय के कारण नाम बदलने या हटाने का अधिकार देती है।
- Three RRBs newly included in the Second Schedule:
 - Bihar Gramin Bank
 - Jammu and Kashmir Grameen Bank
 - West Bengal Gramin Bank
 - Seven erstwhile RRBs excluded due to mergers, including Dakshin Bihar Gramin Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Uttar Bihar Gramin Bank, J & K Grameen Bank, Ellaquai Dehati Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank.
 - Additionally, The Assam Co-operative Apex Bank Ltd has been added to the Second Schedule, making it a Scheduled Bank.
 - इसके अतिरिक्त, असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) revised India's GDP growth forecast for the ongoing financial year to what percentage in its first monetary policy review of 2026?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2026 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर कितना किया?

- A) 7.0%
- B) 7.2%
- C) 7.3%
- D) 7.4%
- E) 7.6%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- On February 6, the Reserve Bank of India (RBI) revised the GDP growth forecast for the ongoing financial year to 7.4%, up from the earlier estimate of 7.3%.
- 6 फरवरी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
- For FY27, real GDP growth for Q1 has been revised to 6.9% from 6.7%.
- FY27 की पहली तिमाही (Q1) के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दी गई है।
- Real GDP growth for Q2 FY27 has been revised to 7.0% from 6.8%, with risks considered evenly balanced.
- FY27 की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.8% से बढ़ाकर 7.0% कर दी गई है, और जोखिम संतुलित माने गए हैं।
- On the supply side, real Gross Value Added (GVA) growth is estimated at 7.3% in FY26.
- आपूर्ति पक्ष पर, FY26 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दर 7.3% अनुमानित की गई है।
- The GVA growth is driven by strong performance in the services sector and a revival in manufacturing.
- GVA वृद्धि में सेवाक्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार का प्रमुख योगदान है।

Ques: As announced by RBI Governor Sanjay Malhotra, what is the maximum

compensation a customer can receive for losses due to small-value digital frauds?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित अनुसार, छोटे मूल्य के डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में ग्राहक को अधिकतम कितनी मुआवजा राशि मिल सकती है?

- A) ₹10,000
- B) ₹15,000
- C) ₹20,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI Governor Sanjay Malhotra announced measures to provide protection and compensation to customers against digital frauds.
- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों को सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करने के उपायों की घोषणा की।
- The announcement was made after the Monetary Policy Committee (MPC) meeting held on 6 February.
- यह घोषणा 6 फरवरी को आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद की गई।
- Customers affected by small-value digital frauds will receive 85% of the fraud amount, subject to a maximum limit of ₹25,000.
- छोटे मूल्य की डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को धोखाधड़ी की राशि का 85% मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 होगी।
- For example, if a person loses ₹50,000 in a digital fraud, 85% equals ₹42,500, but since the cap is ₹25,000, the compensation will be ₹25,000.
- उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को ₹50,000 का नुकसान होता है, तो उसका 85% ₹42,500 होता है, लेकिन अधिकतम सीमा ₹25,000 होने के कारण उसे ₹25,000 ही मिलेगा।
- If a person loses ₹20,000, then 85% equals ₹17,000, which is below the cap; hence the person will receive ₹17,000.

- यदि किसी व्यक्ति को ₹20,000 का नुकसान होता है, तो उसका 85% ₹17,000 होगा, जो सीमा से कम है, इसलिए उसे ₹17,000 मिलेगा।

Ques: SBI recently became India's which most valuable company by market capitalisation?

हाल ही में SBI बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की कौन-सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी?

- A) 2nd
- B) 3rd
- C) 4th
- D) 5th
- E) 6th

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) became India's fourth most valuable company by market capitalisation.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।
- SBI's market capitalisation surged to ₹10.9 lakh crore, allowing it to surpass Tata Consultancy Services (TCS).
- SBI का बाजार पूंजीकरण बढ़कर ₹10.9 लाख करोड़ हो गया, जिससे उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को पीछे छोड़ दिया।
- With this surge, SBI overtook TCS to claim the fourth position among India's top listed firms.
- इस वृद्धि के साथ SBI ने TCS को पीछे छोड़ते हुए भारत की शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों में चौथा स्थान हासिल किया।
- The three most valuable companies in India at present are Reliance Industries, HDFC Bank, and Bharti Airtel.

- वर्तमान में भारत की तीन सबसे मूल्यवान कंपनियाँ हैं – रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और भारती एयरटेल

Ques: Which company received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to participate in Centralized Payment Systems (CPS)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सेंट्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में भागीदारी के लिए किस कंपनी को सैद्धांतिक (In-principle) मंजूरी मिली?

- A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- B) Transcorp International Limited / ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड
- C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- D) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक
- E) Tata Payments Services / टाटा पेमेंट्स सर्विसेज

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Transcorp International Limited received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to participate in Centralized Payment Systems (CPS).
- ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को सेंट्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में भाग लेने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।
- With this authorization, Transcorp will be able to hold and operate a bank account directly with the RBI.
- इस अनुमति के बाद ट्रांसकॉर्प RBI के साथ प्रत्यक्ष रूप से बैंक खाता संचालित कर सकेगा।
- The company will also be allotted its own Indian Financial System Code (IFSC).
- कंपनी को अपना स्वयं का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) भी आवंटित

किया जाएगा।

- Participation in CPS significantly strengthens Transcorp's banking services infrastructure and integration with India's payment ecosystem.
- CPS में भागीदारी ट्रांसकॉर्प की बैंकिंग सेवा संरचना और भारत की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण को मजबूत बनाती है।

Ques: Which financial institution extended a USD 1 billion loan to the State Bank of India (SBI)?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस वित्तीय संस्था ने दिया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- C) Japan International Cooperation Agency (JICA) / जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
- D) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
- E) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Japan's Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) has extended a USD 1 billion (₹7,100 crore) loan to the State Bank of India (SBI).
- जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1 बिलियन डॉलर (₹7,100 करोड़) का ऋण प्रदान किया।
- The loan has a five-year maturity period.
- इस ऋण की परिपक्वता अवधि (Tenure) पाँच वर्ष की है।
- It includes a green shoe option of an additional USD 500 million.
- इसमें अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है।
- The interest rate is set at 90 basis points above the three-month SOFR

(Secured Overnight Financing Rate).

• ब्याज दर तीन-महीने के SOFR (Secured Overnight Financing Rate) से 90 बेसिस पॉइंट अधिक तय की गई है।

Ques: RBI has proposed to increase the aggregate unsecured exposure limit of Urban Cooperative Banks (UCBs) to what percentage of total assets?

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की कुल असुरक्षित ऋण सीमा को कुल परिसंपत्तियों के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है?

- A) 12%
- B) 15%
- C) 18%
- D) 20%
- E) 25%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has proposed to enhance individual and aggregate unsecured loan limits for Urban Cooperative Banks (UCBs).
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए असुरक्षित ऋण सीमाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
 - The aggregate unsecured exposure ceiling may be doubled from 10% to 20% of total assets.
 - कुल असुरक्षित ऋण एक्सपोज़र सीमा को 10% से बढ़ाकर 20% (कुल परिसंपत्तियों का) किया जा सकता है।
- **Individual unsecured loan limits (within the overall ceiling):**
- Tier 1: ₹5 lakh
 - Tier 2: ₹7.5 lakh
 - Tier 3 & 4: ₹10 lakh

• **व्यक्तिगत असुरक्षित ऋण सीमा (कुल सीमा के भीतर):**

- टियर 1: ₹5 लाख
- टियर 2: ₹7.5 लाख
- टियर 3 व 4: ₹10 लाख

• For housing loans (Tier 1 & 2 UCBs), **the** maximum tenor is proposed at 20 years, including moratorium.

• टियर 1 व 2 UCBs के लिए हाउसिंग लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष (मोराटोरियम सहित) प्रस्तावित है।

• The moratorium for Tier 1 & 2 housing loans is capped at 18 months from the first disbursement.

• टियर 1 व 2 के हाउसिंग लोन में मोराटोरियम अधिकतम 18 माह होगा।

• For Tier 3 & 4 UCBs, regulatory restrictions on loan tenor and moratorium are proposed to be removed, subject to Board-approved policies.

• टियर 3 व 4 UCBs को बोर्ड-स्वीकृत नीति के अनुसार लोन अवधि व मोराटोरियम तय करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

• Individual housing loan exposure limits have been revised, going up to ₹3 crore for Tier 4 UCBs.

• व्यक्तिगत हाउसिंग लोन एक्सपोजर सीमा संशोधित कर टियर 4 UCBs के लिए ₹3 करोड़ तक की गई है।

• The loan limit for nominal members to purchase consumer durables is proposed to increase to ₹2.5 lakh per borrower.

• नाममात्र सदस्यों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद हेतु ऋण सीमा ₹2.5 लाख प्रति उधारकर्ता तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank Limited (CUB)?

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (CUB) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Dr. N. Kamakodi / डॉ. एन. कामकोडी

B) R. Vijay Anandh / आर. विजय आनंद

- C) S. Ramesh Kumar / एस. रमेश कुमार
D) R. Subramanian / आर. सुब्रमण्यम
E) P. Mahesh / पी. महेश

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- R. Vijay Anandh has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of City Union Bank Limited (CUB).
- आर. विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (CUB) का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be three years.
- उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- He has replaced Dr. N. Kamakodi in this role.
- उन्होंने इस पद पर डॉ. एन. कामकोडी का स्थान लिया है।

About City Union Bank Limited :

- Established : 1904
- HQ : Kumbakonam, Tamil Nadu
- Tagline : Trust and Excellence since 1904

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) of Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)?

इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) P. R. Jaishankar / पी. आर. जयशंकर
B) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

- C) Rohit Rishi / रोहित ऋषि
- D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
- E) Ashwani Kumar / अश्विनी कुमार

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Rohit Rishi has been appointed as the Managing Director (MD) of Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).
- रोहित ऋषि को इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be three years.
- उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- Prior to this appointment, he served as Executive Director at Bank of Maharashtra.
- इस नियुक्ति से पहले वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के पद पर कार्यरत थे।
- He has replaced P. R. Jaishankar as MD of IIFCL.
- उन्होंने IIFCL के MD पद पर पी. आर. जयशंकर का स्थान लिया है।

Ques: The Indian Army has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with which bank to provide specialised banking services and enhanced insurance benefits to Army personnel?

भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएँ और उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Indian Army and IDFC FIRST Bank have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to provide specialised banking services and enhanced insurance benefits to serving and retired Army personnel.
- भारतीय सेना और IDFC फर्स्ट बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएँ और बेहतर बीमा लाभ देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The MoU has been signed for a period of three years, valid till February 2029.
- यह MoU तीन वर्षों के लिए है और फरवरी 2029 तक मान्य रहेगा।
- Under the agreement, Personal Accidental Insurance cover of ₹60 lakh is provided without mandatory salary or pension credit.
- इस समझौते के तहत ₹60 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बिना वेतन या पेंशन खाते में अनिवार्य जमा के उपलब्ध होगा।
- The insurance benefits are linked to minimum monthly credits instead.
- बीमा लाभों को न्यूनतम मासिक क्रेडिट से जोड़ा गया है।
- Additional benefits include ₹35 lakh nominee cover, ₹1 crore Air Accident Insurance, ₹4 lakh Higher Education Cover, and up to ₹2 lakh Girl Child Marriage Cover.
- अतिरिक्त लाभों में ₹35 लाख का नामिनी कवर, ₹1 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा, ₹4 लाख उच्च शिक्षा कवर, और ₹2 लाख तक कन्या विवाह कवर शामिल हैं।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: As per RBI's draft directions, what action must banks take if mis-selling is established?

RBI के ड्राफ्ट निर्देशों के अनुसार, यदि गलत बिक्री (Mis-selling) साबित होती है तो बैंक को क्या करना होगा?

- A) Issue warning to employee only / केवल कर्मचारी को चेतावनी देना
- B) Pay 10% penalty to RBI / RBI को 10% जुर्माना देना
- C) Refund full amount and compensate for loss / पूरी राशि वापस करना और नुकसान की भरपाई करना
- D) Close customer's account / ग्राहक का खाता बंद करना
- E) No action required / कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive draft directions on advertising, marketing, and sales of financial products and services by banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं।
- The objective of these directions is to prevent mis-selling and compulsory bundling of financial products.
- इन निर्देशों का उद्देश्य गलत बिक्री (Mis-selling) और जबरन बंडलिंग को रोकना है।
- As per the Draft RBI (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Amendment Directions, 2026, banks must seek customer feedback within 30 days of sale.
- ड्राफ्ट RBI (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, बैंकों को बिक्री के 30 दिनों के भीतर ग्राहक से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।
- The new directions are scheduled to come into effect from July 1.
- ये नए निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
- If mis-selling is established, banks must refund the entire amount paid by the customer.

- यदि गलत बिक्री साबित होती है, तो बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी राशि वापस करनी होगी।
- In addition, banks must compensate customers for any financial loss arising due to mis-selling.
- इसके अलावा, गलत बिक्री के कारण हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति भी बैंकों को करनी होगी।
- These provisions aim to strengthen consumer protection and responsible business conduct in the banking sector.
- ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।

Ques: Which international financial institution approved a USD 182 million loan to Assam to strengthen resilience against flooding and riverbank erosion?

असम में बाढ़ और नदी तट कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृत किया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- D) Asian Development Bank (ADB) / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved a USD 182 million loan to Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम को 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण

प्रदान किया है।

- Objective: To expand support for strengthening Assam's resilience to chronic flooding and severe riverbank erosion along the Brahmaputra River.
- उद्देश्य: ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगातार बाढ़ और गंभीर नदी तट कटाव से निपटने की असम की क्षमता को मजबूत करना।
- ADB supports **sustainable, inclusive, and resilient development** across Asia and the Pacific.
- ADB एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत, समावेशी और लचीले विकास को समर्थन देता है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda

Ques: Which two institutions signed an MoU to deepen financial inclusion by providing access to mutual fund products in rural and semi-urban areas?

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and NSE / आरबीआई और एनएसई
- D) SEBI and India Post Payments Bank / सेबी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- E) LIC and NSE / एलआईसी और एनएसई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Posts, Ministry of Communications, and the National Stock Exchange of India Limited (**NSE**) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to deepen financial inclusion.
- संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता (MoU) किया है।
- The initiative aims to provide **access to mutual fund products in rural and semi-urban areas.**
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- The partnership will leverage **India Post's vast network of over 1.64 lakh post offices** across the country.
- इस साझेदारी में इंडिया पोस्ट के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
- The objective is to promote **transparency, investor literacy, and participation in capital market-linked products.**
- इसका उद्देश्य पारदर्शिता, निवेशक साक्षरता और पूंजी बाजार से जुड़े उत्पादों में भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- The MoU is **valid for three years** and can be **renewed by mutual consent** of both parties.
- यह समझौता **तीन वर्षों के लिए वैध है** और आपसी सहमति से नवीनीकृत किया जा सकता है।

National Stock Exchange :

- Established : 1992 (Commenced operations in 1994)
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Ashishkumar Chauhan (Current as of 2026)

Ques: What was the value of the RBI Digital Payments Index (RBI-DPI) for September 2025?

सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) का मान क्या था?

- A) 493.22
- B) 465.33
- C) 516.76
- D) 445.50
- E) 395.57

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has been publishing the **RBI-Digital Payments Index (RBI-DPI)** since **1 January 2021**, with **March 2018** as the base year (Index = 100).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **1 जनवरी 2021** से **RBI-डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI)** प्रकाशित कर रहा है, जिसका आधार वर्ष **मार्च 2018 (इंडेक्स = 100)** है।
- The **RBI-DPI for September 2025 stood at 516.76**, rising from **493.22** in **March 2025**.
- **सितंबर 2025 में RBI-DPI 516.76** रहा, जो **मार्च 2025 के 493.22** से अधिक है।
- This increase reflects **significant growth in digital payment adoption and performance** across India.
- यह वृद्धि देशभर में **डिजिटल भुगतान के उपयोग और प्रदर्शन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी** को दर्शाती है।
- RBI-DPI measures the **extent and depth of digitisation of payments over time**.
- RBI-DPI **समय के साथ डिजिटल भुगतान के विस्तार और गहराई को मापता है।**
- The index is based on **five broad parameters with assigned weights**:
- यह इंडेक्स **पाँच व्यापक मानकों और उनके निर्धारित भार पर आधारित है:**
 - **Payment Enablers – 25%** / पेमेंट एनेबलर्स – 25%
 - **Payment Infrastructure (Demand-side) – 10%** / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डिमांड

साइड) – 10%

– **Payment Infrastructure (Supply-side) – 15%** / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सप्लाई साइड)
– 15%

– **Payment Performance – 45%** / पेमेंट परफॉर्मेंस – 45%

– **Consumer Centricity – 5%** / कंज्यूमर सेंट्रिसिटी – 5%

Ques: What major regulatory change has the RBI introduced for Real Estate Investment Trusts (REITs)?

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) के लिए RBI ने कौन-सा महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव किया है?

A) RBI has allowed foreign banks to directly own REITs / RBI ने विदेशी बैंकों को REITs का प्रत्यक्ष स्वामित्व लेने की अनुमति दी है

B) RBI has permitted banks to lend directly to REITs with prudential safeguards / RBI ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है

C) RBI has removed listing requirements for REITs / RBI ने REITs के लिए लिस्टिंग आवश्यकताएँ समाप्त कर दी हैं

D) RBI has merged REIT regulations with mutual fund norms / RBI ने REIT नियमों को म्यूचुअल फंड नियमों के साथ विलय कर दिया है

E) RBI has restricted REIT funding only to NBFCs / RBI ने REIT फंडिंग को केवल NBFCs तक सीमित कर दिया है

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to lend directly to Real Estate Investment Trusts (REITs) with prudential safeguards.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को

सीधे ऋण देने की अनुमति दी है।

- This move aims to deepen credit access for the real estate sector and address long-term funding needs.

- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और दीर्घकालिक फंडिंग की समस्या को हल करना है।

- Earlier, banks were barred from lending to REITs, though lending to Infrastructure Investment Trusts (InvITs) was permitted.

- पहले बैंकों को REITs को ऋण देने की अनुमति नहीं थी, जबकि InvITs को ऋण देना अनुमत था।

- Existing InvIT lending norms will now be harmonised with safeguards applicable to REITs.

- मौजूदा InvIT ऋण मानदंडों को अब REIT सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जाएगा।

- Currently, India has five listed REITs:

- Brookfield India Real Estate Trust

- Embassy Office Parks REIT

- Mindspace Business Parks REIT

- Nexus Select Trust

- Knowledge Realty Trust

- Earlier, REITs largely relied on short-term bonds (3–5 years) subscribed by mutual funds, NBFCs, and others, leading to long-term funding challenges.

- पहले REITs मुख्यतः अल्पकालिक बॉन्ड (3–5 वर्ष) पर निर्भर थे, जिससे दीर्घकालिक वित्तपोषण की समस्या उत्पन्न होती थी।

Ques: Which organisations signed an agreement to enable UPI-based cross-border merchant payments between India and Malaysia?

भारत और मलेशिया के बीच UPI-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेन्ट भुगतान सक्षम करने के लिए किन संगठनों ने समझौता किया?

A) RBI and Bank Negara Malaysia / आरबीआई और बैंक नेगारा मलेशिया

B) NPCI and Maybank / NPCI और मेबैंक

C) NPCI International Payments Limited and Payments Network Malaysia

- (PayNet) / NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया (PayNet)
- D) SEBI and CIMB Bank / सेबी और सीआईएमबी बैंक
- E) SBI and RHB Bank / एसबीआई और आरएचबी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NIPL) has signed an agreement with Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet).
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया Sdn Bhd (PayNet) के साथ समझौता किया है।
- The agreement aims to enable QR-based cross-border merchant payments between India and Malaysia.
- यह समझौता भारत और मलेशिया के बीच QR-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेन्ट भुगतान को सक्षम बनाने के लिए है।
- In the first phase, Indian travellers visiting Malaysia can scan DuitNow QR codes using Unified Payments Interface (UPI) enabled apps.
- पहले चरण में, मलेशिया जाने वाले भारतीय यात्री UPI-सक्षम ऐप्स से DuitNow QR को स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे।
- This will allow seamless merchant payments directly through UPI apps at DuitNow QR acceptance points.
- इससे DuitNow QR स्वीकार करने वाले व्यापारियों को सीधे UPI ऐप के माध्यम से सहज भुगतान संभव होगा।
- The move strengthens India's global digital payments footprint and promotes UPI as a cross-border payment solution.
- यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत के डिजिटल भुगतान प्रभाव को मजबूत करता है और UPI को क्रॉस-बॉर्डर भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देता है।

Ques: Which two institutions signed an agreement to enable cashless Ayurveda treatment under general health insurance in India?

भारत में सामान्य स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस आयुर्वेद उपचार सक्षम करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता किया?

- A) Ministry of AYUSH and IRDAI / आयुष मंत्रालय और IRDAI
- B) AIIMS New Delhi and General Insurance Council / एम्स नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- C) AIIA New Delhi and General Insurance Council / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- D) NITI Aayog and LIC / नीति आयोग और एलआईसी
- E) National Health Authority and GIC / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और GIC

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi and the General Insurance Council (GIC) signed an agreement to integrate Ayurveda into India's mainstream health insurance ecosystem.
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने आयुर्वेद को भारत की मुख्यधारा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement enables cashless treatment facilities for eligible Ayurveda-based healthcare services across all 32 general insurance companies in India.
- इस समझौते के तहत देश की सभी 32 सामान्य बीमा कंपनियों में पात्र आयुर्वेद आधारित उपचारों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी।
- This move is a major step toward mainstreaming traditional medicine and improving patient access to alternative healthcare systems.
- यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने और रोगियों की पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- AYUSH stands for Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy.

- AYUSH का अर्थ है – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
- The Ministry of AYUSH was established on 9 November 2014 to promote education, research, and development of India's traditional systems of medicine.
- आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- For the first time, the Government of India(GoI) has launched a dedicated Ayush Health Insurance Helpline '1800-11-0008' to support beneficiaries
- भारत सरकार ने पहली बार आयुष स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन '1800-11-0008' शुरू की है।

About All India Institute of Ayurveda :

- Established : 2015
- HQ : New Delhi
- Director : Pradeep Kumar Prajapati

About General Insurance Council :

- Established : 1957
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Tapan Kumar Singhel

Ques: As per the February 2026 draft guidelines, what Credit-Deposit (CD) ratio target has been set for rural and semi-urban branches under the Lead Bank Scheme (LBS)?

फरवरी 2026 के मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार लीड बैंक स्कीम (LBS) के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए CD रेशियो लक्ष्य क्या है?

- A) 40%
- B) 50%

- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Reserve Bank of India (RBI) issued draft guidelines in **February 2026** to streamline the **Lead Bank Scheme (LBS)** with a focus on improving credit flow in rural and semi-urban areas.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में लीड बैंक स्कीम (LBS) को सुव्यवस्थित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।
- As per the draft, **rural and semi-urban branches must achieve a minimum CD ratio of 60%**.
- मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को न्यूनतम 60% CD रेशियो हासिल करना होगा।
- The **Credit-Deposit (CD) ratio** indicates how much of the deposits mobilised by banks are converted into loans; a higher ratio reflects better local credit deployment.
- **क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो** यह दर्शाता है कि बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशि का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया गया है; अधिक CD रेशियो बेहतर स्थानीय ऋण प्रवाह को दर्शाता है।
- **District Consultative Committees (DCCs)** will closely monitor districts where the CD ratio lies between **40% and 60%** to improve performance.
- जिन जिलों में CD रेशियो 40% से 60% के बीच है, उनकी निगरानी **जिला परामर्श समिति (DCC)** द्वारा की जाएगी।
- Districts with a **CD ratio below 20%** will be classified as **'Special Category' districts**, indicating very low credit absorption.
- **20% से कम CD रेशियो** वाले जिलों को **'विशेष श्रेणी'** में रखा जाएगा।
- The guidelines also mandate that **at least 25% of total banking outlets** be opened in **Tier-V and Tier-VI Under-Served Rural Centres (URCs)** to strengthen financial inclusion.
- इसके अलावा **टियर-V और टियर-VI अंडर-सर्व्ड रूरल सेंटर्स (URCs)** में **कम-से-कम**

25% बैंकिंग आउटलेट खोलने का प्रावधान किया गया है।

- Overall, the objective is to **deepen financial inclusion** and **improve credit flow to priority sectors** such as agriculture and MSMEs.
- समग्र रूप से, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहरा करना और प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाना है।

Ques: Who has received a three-year extension as the Managing Director & CEO of AU Small Finance Bank?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे तीन वर्ष का विस्तार मिला है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) **Sanjay Agarwal / संजय अग्रवाल**
- C) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Chandra Shekhar Ghosh / चंद्रशेखर घोष

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank announced that Reserve Bank of India (**RBI**) has approved the reappointment of Sanjay Agarwal as its Managing Director & Chief Executive Officer.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**) ने संजय अग्रवाल की एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- The extension is for a **further period of three years**, effective from **April 19**.
- यह विस्तार **19 अप्रैल** से प्रभावी **तीन वर्षों** के लिए है।
- The reappointment had earlier been approved by the **Board (October 17, 2025)** and **shareholders (December 26, 2025)**, subject to RBI confirmation.
- पुनर्नियुक्ति को पहले **बोर्ड (17 अक्टूबर 2025)** और **शेयरधारकों (26 दिसंबर 2025)** से

मंजूरी मिल चुकी थी, जो RBI की पुष्टि के अधीन थी।

- Recently, **AU Small Finance Bank** also received **in-principle approval from RBI** to transition into a **universal bank**.

- हाल ही में **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक** को **यूनिवर्सल बैंक** में परिवर्तित होने के लिए **RBI** से **सैद्धांतिक मंजूरी** भी प्राप्त हुई है।

Ques: As per the revised norms, what is the maximum aggregate exposure banks can extend towards acquisition (M&A) financing?

संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक अधिग्रहण (M&A) फाइनेंसिंग के लिए अधिकतम कितना कुल एक्सपोजर दे सकते हैं?

- A) 10% of capital base / पूंजी आधार का 10%
- B) 15% of capital base / पूंजी आधार का 15%
- C) **20% of capital base / पूंजी आधार का 20%**
- D) 25% of capital base / पूंजी आधार का 25%
- E) 30% of capital base / पूंजी आधार का 30%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (**RBI**) has allowed banks to extend aggregate exposure up to **20% of their eligible capital base** for acquisition (M&A) financing, increased from the earlier proposed **10%**.

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने अधिग्रहण फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को अपनी पात्र पूंजी आधार का **20%** तक कुल एक्सपोजर देने की अनुमति दी है, जो पहले प्रस्तावित **10%** था।

- Banks are now permitted to finance **acquisitions of unlisted companies**, subject to prescribed conditions.

- अब बैंकों को कुछ शर्तों के तहत **अनलिस्टेड कंपनियों के अधिग्रहण** के लिए फाइनेंसिंग

की अनुमति दी गई है।

- The target unlisted company must have a **minimum net worth of ₹500 crore**, be **profit-making for the last three years**, and possess an **investment-grade credit rating (BBB– or above)**.
- लक्षित अनलिस्टेड कंपनी की **न्यूनतम नेटवर्थ ₹500 करोड़**, पिछले तीन वर्षों से लाभ में होना, और **निवेश-ग्रेड रेटिंग (BBB– या उससे ऊपर)** होना अनिवार्य है।
- The permissible portion of bank financing has been increased to **75% of the acquisition value** from the earlier proposed **70%**.
- बैंक फाइनेंसिंग की अनुमत सीमा को पहले प्रस्तावित **70%** से बढ़ाकर **अधिग्रहण मूल्य का 75%** कर दिया गया है।
- The remaining **25%** of the acquisition cost must be funded by the acquirer through **internal accruals or fresh equity issuance**.
- शेष **25%** राशि अधिग्रहणकर्ता को **आंतरिक संसाधनों या नई इक्विटी जारी कर जुटानी** होगी।
- These revisions aim to provide **greater flexibility to banks** while ensuring **prudent risk management** in acquisition financing.
- इन संशोधनों का उद्देश्य **संतुलित जोखिम प्रबंधन** बनाए रखते हुए बैंकों को **अधिक लचीलापन** प्रदान करना है।

Ques: Who has been appointed as the Chairman of GIFT City by the Government of Gujarat?

गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- B) Uday Kotak / उदय कोटक
- C) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- D) Rajeev Jain / राजीव जैन
- E) Ajay Seth / अजय सेठ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Government of Gujarat appointed Uday Kotak as the Chairman of Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd (**GIFT City**).
- गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (**GIFT City**) का चेयरमैन नियुक्त किया।
- Uday Kotak is the **Founder and Director** of Kotak Mahindra Bank.
- वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक एवं निदेशक हैं।
- He replaced Hasmukh Adhia in this position.
- उन्होंने इस पद पर हसमुख अधिया का स्थान लिया।
- As per the resolution of the **Urban Development Department of Gujarat**, he will assume charge **with immediate effect**.
- गुजरात के शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, वे तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करेंगे।

Ques: Which bank was fined ₹63.60 lakh by the Reserve Bank of India (RBI) for non-compliance with regulatory norms?

नियामकीय मानदंडों का पालन न करने पर RBI द्वारा ₹63.60 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया?

- A) Bank of Maharashtra / बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- B) DCB Bank / डीसीबी बैंक
- C) **CSB Bank / सीएसबी बैंक**
- D) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India imposed monetary penalties on **three banks** for non-

compliance with its regulatory guidelines.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर तीन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- A fine of ₹32.50 lakh was imposed on Bank of Maharashtra.
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹32.50 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- A penalty of ₹29.60 lakh was imposed on DCB Bank.
- डीसीबी बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- The highest penalty of ₹63.60 lakh was imposed on CSB Bank.
- सबसे अधिक ₹63.60 लाख का जुर्माना सीएसबी बैंक पर लगाया गया।
- The penalties were related to non-compliance with RBI's regulatory norms.
- ये सभी जुर्माने RBI के नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित थे।

Ques: Punjab National Bank (PNB) announced which themed half marathon to honour the Indian Armed Forces and promote fitness?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किस थीम आधारित हाफ मैराथन की घोषणा की?

- A) PNB Fit India Run / पीएनबी फिट इंडिया रन
- B) PNB Veer Run / पीएनबी वीर रन
- C) PNB Soldierathon 2026 / पीएनबी सोल्जरार्थॉन 2026
- D) PNB National Pride Marathon / पीएनबी नेशनल प्राइड मैराथन
- E) PNB Unity Run / पीएनबी यूनिटी रन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) announced the 'PNB Soldierathon 2026', a themed half marathon, at its Corporate Office in Dwarka, New Delhi.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने द्वारका, नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में

थीम आधारित हाफ मैराथन 'PNB सोल्जरार्थॉन 2026' की घोषणा की।

- The initiative aims to honour the Indian Armed Forces.
- इस पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देना है।
- It also seeks to promote fitness and a healthy lifestyle among citizens.
- यह नागरिकों में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- The event encourages discipline, national pride, and stronger community engagement.
- यह आयोजन अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
- The Soldierathon is part of PNB's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives and supports nation-building efforts.
- सोल्जरार्थॉन PNB की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल का हिस्सा है और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का समर्थन करता है।

Ques: What did the Ministry of Finance state regarding Foreign Direct Investment (FDI) equity inflows into India's banking sector in FY 2024–25?

वित्त वर्ष 2024–25 में बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह को लेकर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

- A) It increased sharply compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें तेज़ वृद्धि हुई
- B) It remained unchanged from FY23 / यह FY23 के समान ही रहा
- C) It declined significantly compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें भारी गिरावट आई
- D) It crossed USD 1 billion / यह 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया
- E) Data was not disclosed / आंकड़े जारी नहीं किए गए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Ministry of Finance stated that **FDI equity inflows into the banking sector declined to USD 115 million in FY 2024–25**, compared to **USD 898 million in FY 2022–23**.

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में **FDI इक्विटी प्रवाह FY 2024–25 में घटकर 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया**, जबकि **FY 2022–23 में यह 898 मिलियन डॉलर था**।

- FDI inflows include **equity inflow, equity capital of unincorporated bodies, re-invested earnings, and other capital**.

- FDI प्रवाह में **इक्विटी निवेश, अविनियमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय, और अन्य पूंजी शामिल होती है**।

- Among public sector banks, State Bank of India recorded the **highest foreign shareholding**.

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सबसे अधिक विदेशी शेयरधारिता दर्ज की गई**।

- This foreign shareholding includes investments from:

- **Foreign Direct Investment (FDI) / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

- **Foreign Portfolio Investors / Foreign Institutional Investors (FPI/FII) / विदेशी पोर्टफोलियो/संस्थागत निवेशक**

- **Non-Resident Indians (NRIs) / अनिवासी भारतीय**

- As per the Reserve Bank of India Master Directions on '*Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies*', **prior RBI approval is mandatory for acquiring 5% or more of the paid-up capital** of a banking company.

- **RBI के 'बैंकिंग कंपनियों में शेयर या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण एवं धारण संबंधी मास्टर निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक की चुकता पूंजी का 5% या उससे अधिक अधिग्रहण करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति अनिवार्य है**।

Rankings with their foreign Shareholding :

1 State Bank of India - 11.07%

2 Canara Bank - 10.55%

3 Bank of Baroda - 9.43%

- 4 Union Bank of India - 7.48%
5 Punjab National Bank - 5.85%
-

Ques: According to a report by State Bank of India (SBI), what percentage of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात का कितना प्रतिशत अब शून्य शुल्क (Zero Tariff) का लाभ प्राप्त करेगा?

- A) 50%
B) 60%
C) 65%
D) 70%
E) 75%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- According to a report by State Bank of India (SBI), nearly 75% of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत के लगभग 75% कृषि निर्यात पर अब शून्य शुल्क लगेगा।
- Agricultural products worth \$1.36 billion will get access to the US market with zero additional duty.
- \$1.36 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों को अमेरिका में बिना अतिरिक्त शुल्क के प्रवेश मिलेगा।
- Products worth \$1.035 billion are assured zero reciprocal tariff treatment.
- \$1.035 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों को शून्य पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariff) की गारंटी दी गई है।
- This move strengthens India's agricultural trade surplus of around \$1.3 billion with the United States.
- यह कदम अमेरिका के साथ भारत के लगभग \$1.3 अरब के कृषि व्यापार अधिशेष को और मज़बूत करता है।

- The zero-tariff access is expected to improve price competitiveness and boost export volumes.
- शून्य शुल्क व्यवस्था से भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा और निर्यात मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है।

Major Beneficiary Sectors / प्रमुख लाभार्थी क्षेत्र:

Rice:

- US global rice imports stand at \$1.378 billion, with imports from India at \$341 million.
- The US rice import market share of India is 24.7%.
- चावल: अमेरिका का कुल चावल आयात \$1.378 अरब है, जिसमें भारत से \$341 मिलियन का आयात होता है और भारत की हिस्सेदारी 24.7% है।

Fishery Sector:

- US global imports of fish and aquatic invertebrates are valued at \$18.84 billion.
- Imports from India amount to \$1.8 billion, giving India a 9.6% share.
- मत्स्य क्षेत्र: अमेरिका का कुल आयात \$18.84 अरब है, जिसमें भारत से \$1.8 अरब का आयात होता है और हिस्सेदारी 9.6% है।

Tea, Coffee and Spices:

- US global imports are \$14.02 billion, with India exporting \$396 million.
- India's share stands at 2.8%.
- चाय, कॉफी और मसाले: अमेरिका का कुल आयात \$14.02 अरब है, जिसमें भारत से \$396 मिलियन का आयात होता है और हिस्सेदारी 2.8% है।

Overall Agricultural Trade Position / समग्र कृषि व्यापार स्थिति:

- Across selected categories, total US agricultural imports are \$81.95 billion.
- Imports from India amount to \$2.89 billion, giving India an overall share of 3.5%.
- चयनित श्रेणियों में अमेरिका का कुल कृषि आयात \$81.95 अरब है, जिसमें भारत से

\$2.89 अरब का आयात होता है और कुल हिस्सेदारी 3.5% है।

Ques: Which organization introduced a Braille-enabled Premier Credit Card to support visually impaired users in India?

दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड किस संस्था ने पेश किया?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- C) BOBCARD Limited (Bank of Baroda) / बॉबकार्ड लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा)
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- BOBCARD Limited, the credit card arm of Bank of Baroda, introduced a Braille-enabled version of its Premier Credit Card at an event held in Manipal, Karnataka.
- बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड इकाई BOBCARD लिमिटेड ने कर्नाटक के मणिपाल में आयोजित कार्यक्रम में ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- The card incorporates Braille elements to help visually impaired users identify and use the card with greater ease and confidence during everyday transactions.
- इस कार्ड में ब्रेल चिह्न शामिल किए गए हैं, जिससे दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता दैनिक लेन-देन में कार्ड को आसानी और आत्मविश्वास के साथ पहचान व उपयोग कर सकें।
- It also provides accelerated rewards on travel, lifestyle, dining, and international transactions.
- इसमें यात्रा, लाइफस्टाइल, डाइनिंग और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर तेज़ रिवॉईस मिलते हैं।

- The card offers travel benefits, including complimentary domestic airport lounge access and curated lifestyle privileges.
- कार्ड में घरेलू हवाई अड्डों के लाउंज की निःशुल्क सुविधा और विशेष लाइफस्टाइल लाभ भी शामिल हैं।

Braille-Enabled Card Providers in India | भारत में ब्रेल-सक्षम कार्ड प्रदाता

- Punjab National Bank (PNB)
 - PNB Braille Credit Card (Credit Card)
 - First major bank to launch a dedicated Braille Credit Card (December 2025).
 - ब्रेल-सक्षम समर्पित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बड़ा बैंक।
- BOBCARD Limited / Bank of Baroda
 - bob inSIGHT Debit Card (Debit Card)
 - Features tactile dots and a rounded notch for orientation.
 - पहचान हेतु स्पर्शनीय डॉट्स और राउंडेड नॉच की सुविधा।
- State Bank of India (SBI)
 - Braille Debit Card (Debit Card)
 - Provides Braille-enabled cards on request for visually impaired account holders.
 - दृष्टिबाधित खाताधारकों को अनुरोध पर ब्रेल-सक्षम कार्ड उपलब्ध कराता है।

Ques: What was the year-on-year (YoY) growth in Currency in Circulation (CiC) in January 2026?

जनवरी 2026 में प्रचलन में मुद्रा (CiC) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 5.3%
- B) 8.5%
- C) 9.7%
- D) 11.1%
- E) 14.4%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या :

- **Currency in Circulation (CiC)** touched a **record high of ₹40 lakh crore** for the month ending **January 2026**.
- **जनवरी 2026** को समाप्त माह में प्रचलन में मुद्रा (CiC) ₹40 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
- CiC registered a **year-on-year growth of 11.1%**, significantly higher than **5.3%** recorded in January last year.
- CiC में **11.1% की साल-दर-साल वृद्धि** दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह यह **5.3%** थी।
- On a **year-to-date (YTD)** basis, CiC increased by **₹2.76 lakh crore**, which is about **3.11 times higher** than the increase during the same period last year.
- **वर्ष-से-तारीख (YTD)** आधार पर CiC में ₹2.76 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग **3.11 गुना अधिक** है।
- Despite the rise in cash usage, the **cash-to-GDP ratio declined to 11% in FY26 (so far)**, compared to **14.4% in FY21**, indicating deeper financialisation and digital payments penetration.
- नकदी प्रचलन बढ़ने के बावजूद, **FY26 (अब तक)** में नकद-से-GDP अनुपात घटकर **11%** रह गया, जो **FY21 में 14.4%** था।
- These findings were reported by SBI Research.
- यह आँकड़े SBI Research द्वारा जारी किए गए हैं।

Ques: Who released the latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 (July–September 2025)? Q2 FY 2025–26 (जुलाई–सितंबर 2025) के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया?

- A) Amitabh Kant / अमिताभ कांत
- B) Rajiv Kumar / राजीव कुमार
- C) Suman Bery / सुमन बेरी
- D) Sanjeev Sanyal / संजीव सान्याल
- E) Arvind Panagariya / अरविंद पनगढ़िया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 was released by Suman Bery, Vice-Chairman of NITI Aayog.
- Q2 FY 2025–26 के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
- The report notes that global trade growth has moderated but remains positive, with services trade outperforming goods trade.
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन सकारात्मक बनी हुई है, जहाँ सेवा व्यापार वस्तु व्यापार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- India’s trade expansion in Q2 FY26 was driven by export-led momentum, with services and merchandise exports growing by around 8.5%, faster than imports.
- Q2 FY26 में भारत का व्यापार विस्तार निर्यात-आधारित गति से संचालित रहा, जहाँ सेवा और वस्तु निर्यात लगभग 8.5% बढ़े, जो आयात वृद्धि से अधिक था।
- The report highlights India’s increasing alignment with regional value chains and new trade corridors.
- रिपोर्ट में क्षेत्रीय वैल्यू चेन और नए व्यापार गलियारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है।
- E-commerce exports, though currently modest, are projected to contribute 20–30% of India’s merchandise exports by 2030.
- ई-कॉमर्स निर्यात वर्तमान में सीमित हैं, लेकिन 2030 तक भारत के वस्तु निर्यात में 20–30% योगदान देने का अनुमान है।
- Electronics exports grew nearly fivefold between 2016 and 2024 to reach USD 42.1 billion, with India’s global electronics demand share growing at a CAGR of 17.2%, far above the global average of 4.4%.
- 2016 से 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग पाँच गुना बढ़कर 42.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मांग में भारत की हिस्सेदारी 17.2% CAGR से बढ़ी, जो वैश्विक औसत 4.4% से कहीं अधिक है।

Ques: NPCI extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors attending which event?

NPCI ने 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए किया?

- A) G20 Summit 2026 / G20 शिखर सम्मेलन 2026
- B) India AI Impact Summit 2026 / इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026
- C) Digital India Conference 2026 / डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2026
- D) Vibrant Gujarat Summit 2026 / वाइब्रेंट गुजरात समिट 2026
- E) World Economic Forum 2026 / वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has extended the **'UPI One World' wallet service for international visitors from 40+ countries.**
- National Payments Corporation of India (NPCI) ने **40 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किया है।**
- This facility is specifically available for attendees of the **India AI Impact Summit 2026, held from 16–20 February 2026 in New Delhi.**
- यह सुविधा **16–20 फरवरी 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में भाग लेने वाले आगंतुकों के लिए उपलब्ध है।**
- Under this **pilot initiative**, foreign travellers can make **seamless, secure, real-time Person-to-Merchant (P2M) payments** using UPI while staying in India.
- इस **पायलट पहल** के तहत विदेशी यात्री भारत में रहते हुए **सहज, सुरक्षित और रियल-टाइम Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान** कर सकते हैं।
- The initiative aims to **promote digital payments, showcase India's fintech leadership, and enhance convenience for inbound tourists and global delegates.**
- इस पहल का उद्देश्य **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भारत की फिनटेक क्षमता को प्रदर्शित करना और विदेशी पर्यटकों व वैश्विक प्रतिनिधियों की सुविधा बढ़ाना है।**

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) granted final approval to Bain Capital affiliates to acquire joint control and up to what percentage stake in Manappuram Finance?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी?

- A) 26%
- B) 33%
- C) 41.66%
- D) 49%
- E) 51%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has granted final approval to affiliates of Bain Capital to acquire joint control and up to 41.66% stake in Kerala-based Manappuram Finance.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को केरल स्थित मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम 41.66% हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी है।
- This approval clears the way for the completion of Bain Capital's ₹4,385 crore investment in the gold loan-focused NBFC.
- इस मंजूरी से गोल्ड लोन पर केंद्रित NBFC में बेन कैपिटल के ₹4,385 करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- Bain Capital was founded in 1984 and is headquartered in Boston, Massachusetts, USA.
- बेन कैपिटल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में स्थित है।
- Manappuram Finance was originally founded in 1949 and is headquartered at Valapad in the Thrissur district of Kerala.

- मणप्पुरम फाइनेंस की मूल स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर ज़िले के वलापाड में स्थित है।
- It is a Non-Deposit Accepting Loan Company and is classified as a Systemically Important Non-Banking Financial Company (NBFC-ND-SI).
- यह एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली ऋण कंपनी है और इसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- Deepak Reddy assumed charge as the Chief Executive Officer (CEO) of Manappuram Finance on August 1, 2025.
- दीपक रेड्डी ने 1 अगस्त 2025 को मणप्पुरम फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।

Ques: NPCI has partnered with which company to advance its sovereign AI model for digital payments?

NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए सॉवरेन AI मॉडल को आगे बढ़ाने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Nvidia / एनवीडिया
- B) Google / गूगल
- C) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- D) IBM / आईबीएम
- E) Amazon / अमेज़न

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has partnered with Nvidia to scale and advance a sovereign AI model for India's digital payments ecosystem.
- NPCI ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए सॉवरेन AI मॉडल को विकसित और विस्तारित करने हेतु Nvidia के साथ साझेदारी की है।
- The initiative focuses on building AI capabilities aligned with India's

regulatory framework and data sovereignty requirements.

- यह पहल भारत की नियामकीय व्यवस्था और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अनुरूप AI क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।
- NPCI will leverage Nvidia's advanced AI and accelerated computing platforms, including Nvidia Nemotron models.
- NPCI, Nvidia के उन्नत AI और accelerated computing प्लेटफॉर्म, जैसे Nvidia Nemotron मॉडल्स, का उपयोग करेगा।
- The collaboration aims to enhance trust, resilience, security, and efficiency in large-scale real-time payment systems.
- इस सहयोग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रियल-टाइम भुगतान प्रणालियों में भरोसा, लचीलापन, सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करना है।

Ques: What key change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) को लेकर कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Banned the use of DLGs permanently / DLG के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया
- B) Allowed DLGs only for banks, not NBFCs / DLG केवल बैंकों के लिए अनुमति दी, NBFCs के लिए नहीं
- C) Restored the use of DLGs for NBFCs in loan loss provisioning / NBFCs को ऋण हानि प्रावधान में DLG शामिल करने की अनुमति दी
- D) Increased the cap on DLGs to 10% of loan portfolio / DLG की सीमा 10% तक बढ़ाई
- E) Allowed DLGs only for government-backed fintechs / DLG केवल सरकारी समर्थित फिनटेक्स के लिए अनुमति दी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has restored the use of Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders, reversing its curbs imposed in May 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेते हुए गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) के उपयोग को बहाल कर दिया है।
- Under the revised framework, NBFCs can again factor in DLGs while calculating loan loss provisions, and the changes take effect immediately.
- संशोधित ढांचे के तहत NBFCs अब ऋण हानि प्रावधान की गणना में DLG को शामिल कर सकती हैं और यह व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।
- The guarantee must be an integral part of the loan arrangement and cannot be treated as a separate standalone protection.
- यह गारंटी ऋण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और इसे अलग सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- Loss estimates must be updated every time the DLG is invoked, as the level of protection reduces with each utilisation.
- प्रत्येक बार DLG के उपयोग पर हानि अनुमान को अपडेट करना होगा, क्योंकि हर उपयोग के साथ सुरक्षा घटती जाती है।
- DLGs are risk-sharing mechanisms widely used in digital lending and co-lending models, usually capped at 5% of the loan portfolio and often backed by fixed deposits from fintech partners.
- DLG जोखिम-साझाकरण तंत्र हैं, जो डिजिटल लेंडिंग और सह-ऋण मॉडल में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, आमतौर पर ऋण पोर्टफोलियो के 5% तक सीमित होते हैं और अक्सर फिनटेक भागीदारों की फिक्स्ड डिपॉजिट से समर्थित होते हैं।
- Earlier, in May 2025, RBI had required NBFCs to exclude fintech-provided DLGs from provisioning calculations, leading to higher credit costs and reduced profitability.
- इससे पहले मई 2025 में RBI ने NBFCs को प्रावधान गणना से फिनटेक-प्रदत्त DLG को बाहर रखने का निर्देश दिया था, जिससे क्रेडिट लागत बढ़ी और लाभप्रदता में गिरावट आई थी।

Ques: Why has SEBI constituted a working group recently?

SEBI ने हाल ही में कार्यसमूह क्यों गठित किया है?

- A) To regulate cryptocurrency exchanges / क्रिप्टोकॉरेंसी एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए
- B) To review the framework for ESG Rating Providers / ESG रेटिंग प्रदाताओं के ढांचे की समीक्षा के लिए
- C) To revise mutual fund taxation rules / म्यूचुअल फंड कर नियमों में संशोधन के लिए
- D) To promote IPO listings / IPO लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए
- E) To regulate commodity markets / क्मोडिटी बाजार को विनियमित करने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a dedicated working group to review the regulatory framework for ESG Rating Providers (ERPs).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने ESG रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यसमूह का गठन किया है।
- The move follows feedback from market participants regarding ESG rating practices.
- यह कदम बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के बाद उठाया गया है।
- The panel includes representatives from issuers, investors, domestic & global ERPs, ESG analysts, legal experts, and academia.
- इस पैनल में इश्यूअर्स, निवेशकों, घरेलू व वैश्विक ERPs, ESG विश्लेषकों, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- The group will review existing regulations, assess global developments, and recommend measures to enhance transparency and reliability in ESG ratings.
- यह कार्यसमूह मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगा, वैश्विक विकास का आकलन करेगा और ESG रेटिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उपाय सुझाएगा।

Ques: Indian Overseas Bank (IOB) expanded its start-up focused banking network by launching exclusive branches in which cities?

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्टार्ट-अप केंद्रित बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किन शहरों में विशेष शाखाएँ शुरू करके किया?

- A) Chennai, Hyderabad, Pune / चेन्नई, हैदराबाद, पुणे
- B) Delhi, Mumbai, Bengaluru / दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु
- C) Kolkata, Ahmedabad, Jaipur / कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर
- D) Kochi, Trivandrum, Coimbatore / कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोयंबटूर
- E) Noida, Gurugram, Faridabad / नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Indian Overseas Bank has expanded its dedicated Start-up Banking Network by launching exclusive start-up focused branches in Delhi, Mumbai, and Bengaluru.
- इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष स्टार्ट-अप केंद्रित शाखाएँ शुरू करके अपने स्टार्ट-अप बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है।
- This expansion builds on the success of its first start-up focused branch in Chennai, which was launched in June 2024.
- यह विस्तार जून 2024 में चेन्नई में शुरू की गई पहली स्टार्ट-अप शाखा की सफलता पर आधारित है।
- The initiative was announced on the occasion of the 90th Foundation Day of Indian Overseas Bank.
- यह पहल इंडियन ओवरसीज बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की गई।
- These specialised branches offer a tailored Startup Current Account with benefits such as waiver of Quarterly Average Balance (QAB) for the first 18 months.
- इन विशेष शाखाओं में स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष करंट अकाउंट उपलब्ध है, जिसमें

पहले 18 महीनों तक तिमाही औसत शेष राशि (QAB) से छूट दी गई है।

- Additional features include 200 free cheque leaves per month and free NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
- अतिरिक्त सुविधाओं में प्रति माह 200 निःशुल्क चेक पत्ते और निःशुल्क NEFT, RTGS तथा IMPS लेन-देन शामिल हैं।
- The bank also launched 'IOB Gram Sweekar', a rural outreach programme aimed at strengthening credit delivery, enhancing financial literacy, and ensuring universal access to flagship banking products.
- बैंक ने 'IOB ग्राम स्वीकर' नामक ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण को मजबूत करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और प्रमुख बैंकिंग उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- Under this initiative, IOB has adopted 90 Gram Panchayats across 14 districts in Tamil Nadu and Kerala.
- इस पहल के तहत IOB ने तमिलनाडु और केरल के 14 ज़िलों में 90 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है।

Ques: What is the key impact of the Reserve Bank of India's (RBI) new lending norms for capital market intermediaries effective from April 1?

1 अप्रैल से प्रभावी RBI के नए ऋण नियमों का पूंजी बाजार मध्यस्थों पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेगा?

- A) Banks can freely lend for brokers' proprietary trading / बैंक ब्रोकरों के स्वयं के ट्रेडिंग के लिए स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकेंगे
- B) Unsecured loans to stock brokers are permitted / स्टॉक ब्रोकरों को बिना गारंटी ऋण देने की अनुमति होगी
- C) All credit to securities firms must be fully collateral-backed / प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया हर ऋण पूरी तरह जमानत-आधारित होगा
- D) Bank guarantees for proprietary trades need no cash collateral / प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए बैंक गारंटी में नकद जमानत की आवश्यकता नहीं होगी
- E) Commodity brokers are exempted from the new norms / क्मोडिटी ब्रोकरों को

नए नियमों से छूट दी गई है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has tightened lending norms for capital market intermediaries, including stock and commodity brokers involved in proprietary trading.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में लगे स्टॉक और क्मोडिटी ब्रोकर्सों सहित पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए ऋण नियम सख्त कर दिए हैं।
- Under the new prudential framework, all loans to securities firms must be fully backed by collateral, eliminating unsecured exposure to speculative activities.
- नए सावधानीपूर्ण ढांचे के तहत प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया प्रत्येक ऋण पूरी तरह जमानत से सुरक्षित होना अनिवार्य होगा, जिससे सट्टात्मक गतिविधियों में बिना गारंटी जोखिम समाप्त होगा।
- Banks are prohibited from lending for brokers' own-account (proprietary) trading or for investments made by brokers.
- बैंकों को ब्रोकर्सों की स्वयं की ट्रेडिंग या उनके निवेश के लिए ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Bank guarantees issued for proprietary trades must be fully secured, with at least 50% collateral in cash and the remaining portion in cash equivalents or government securities.
- प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए जारी बैंक गारंटी पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% जमानत नकद में और शेष नकद समकक्ष या सरकारी प्रतिभूतियों में हो।
- These measures aim to curb excessive risk-taking by capital market intermediaries and strengthen financial stability.
- इन उपायों का उद्देश्य पूंजी बाजार मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने पर रोक लगाना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

Ques: From which date are bank loans to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for on-lending to cooperative societies eligible for Priority Sector Lending (PSL) classification?

किस तिथि से सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

- A) 1 April 2025 / 1 अप्रैल 2025
- B) 1 July 2025 / 1 जुलाई 2025
- C) 19 January 2026 / 19 जनवरी 2026
- D) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
- E) 26 January 2026 / 26 जनवरी 2026

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, announced that loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation for on-lending to cooperative societies will be eligible for Priority Sector Lending classification with effect from 19 January 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह घोषणा की कि सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण 19 जनवरी 2026 से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्य होंगे।
- This PSL classification applies to banks other than Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, and Local Area Banks.
- यह प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और लोकल एरिया बैंकों पर लागू नहीं होगा।
- Urban Cooperative Banks have been permitted to open new branches, and their housing loan limit has been enhanced from 10% to 25% of total loans and advances.
- शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गई है तथा उनके आवास

ऋण की सीमा कुल ऋण एवं अग्रिमों के 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।

- The Banking Regulation Act has been amended to increase the tenure of directors of Cooperative Banks from 8 years to 10 years.
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन कर सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- The National Urban Co-operative Finance and Development Corporation Limited has been established as an umbrella organisation for Urban Cooperative Banks to provide IT infrastructure and operational support.
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी अवसंरचना और परिचालन सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है।
- A Shared Services Entity named Sahakar Sarthi has been set up to provide technological services to Rural Cooperative Banks, and these banks have been included under the Integrated Ombudsman Scheme of RBI.
- ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएँ देने के लिए 'सहकार सारथी' नामक साझा सेवा इकाई स्थापित की गई है तथा इन्हें RBI की एकीकृत लोकपाल योजना में शामिल किया गया है।

Ques : RBI has deferred implementation of Unique Transaction Identifier (UTI) for OTC derivatives till which date?

RBI ने OTC डेरिवेटिव्स के लिए UTI लागू करने की समयसीमा किस तिथि तक टाली है?

- A) January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- B) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026
- C) January 1, 2027 / 1 जनवरी 2027
- D) March 31, 2027 / 31 मार्च 2027
- E) December 31, 2026 / 31 दिसंबर 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has deferred the implementation of the Unique Transaction Identifier (UTI) for all Over-the-Counter (OTC) derivatives to January 1, 2027.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी OTC डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांज़ैक्शन आईडी (UTI) लागू करने की समयसीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है।
- The UTI system will help regulators obtain a comprehensive view of the OTC derivatives market and enhance transparency.
- UTI प्रणाली से नियामकों को OTC डेरिवेटिव्स बाजार की समग्र जानकारी प्राप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- The mandate will apply to transactions entered into on or after January 1, 2027.
- यह अनिवार्यता 1 जनवरी 2027 या उसके बाद किए गए लेनदेन पर लागू होगी।
- Currently, OTC transactions are reported to the Trade Repository managed by Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR).
- वर्तमान में OTC लेनदेन की रिपोर्टिंग Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR) द्वारा संचालित ट्रेड रिपॉजिटरी में की जाती है।
- Covered instruments include rupee interest rate derivatives, forward contracts in government securities, foreign currency derivatives, foreign currency interest rate derivatives, and credit derivatives.
- इसमें रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स, सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स शामिल हैं।

Ques: DBS Bank Limited partnered with Visa to pilot agent-initiated payments under which innovative payment framework?

डीबीएस बैंक लिमिटेड ने एजेंट-इनिशिएटेड पेमेंट्स के पायलट के लिए वीज़ा के साथ किस नवोन्मेषी भुगतान ढांचे के तहत साझेदारी की है?

- A) Visa Secure Pay / वीज़ा सिक्क्योर पे
- B) Visa Token Service / वीज़ा टोकन सेवा
- C) Visa Intelligent Commerce (VIC) / वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स
- D) Visa Direct / वीज़ा डायरेक्ट
- E) Visa PayWave AI / वीज़ा पेवेव एआई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- DBS Bank Limited, Southeast Asia's largest lender, entered into a strategic partnership with Visa to pilot agent-initiated payments under Visa Intelligent Commerce (VIC).
- दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS बैंक लिमिटेड ने वीज़ा के साथ Visa Intelligent Commerce (VIC) के तहत एजेंट-इनिशिएटेड भुगतान के पायलट के लिए रणनीतिक साझेदारी की।
- With this initiative, DBS became the first issuer in the Asia-Pacific region to operationalise real-world agentic commerce use cases.
- इस पहल के साथ DBS एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला जारीकर्ता बना जिसने वास्तविक दुनिया में एजेंटिक कॉमर्स उपयोग-मामलों को लागू किया।
- Visa Intelligent Commerce (VIC) is a payment framework that enables AI agents to securely initiate and complete transactions on behalf of consumers.
- Visa Intelligent Commerce (VIC) एक भुगतान ढांचा है जो उपभोक्ताओं की ओर से AI एजेंट्स को सुरक्षित रूप से लेन-देन शुरू करने और पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- Under the pilot, AI agents completed food and beverage purchases using DBS/POSB credit and debit cards, with payments processed through secure, issuer-approved flows.
- इस पायलट के तहत AI एजेंट्स ने DBS/POSB क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके खाद्य एवं पेय पदार्थों की खरीद की, जिनके भुगतान सुरक्षित और जारीकर्ता-स्वीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए।
- Explicit customer consent was maintained throughout the transactions.
- पूरे लेन-देन के दौरान ग्राहक की स्पष्ट सहमति सुनिश्चित की गई।

Ques: What is FiMI launched by NPCI?

NPCI द्वारा लॉन्च किया गया FiMI क्या है?

- A) A new UPI payment app / एक नया UPI पेमेंट ऐप
- B) A blockchain-based settlement system / ब्लॉकचेन आधारित सेटलमेंट सिस्टम
- C) A domain-specific AI language model for payments / भुगतान प्रणाली के लिए डोमेन-विशिष्ट AI भाषा मॉडल
- D) A new digital wallet / एक नया डिजिटल वॉलेट
- E) A credit scoring platform / एक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- National Payments Corporation of India (NPCI) launched FiMI (Finance Model for India) at the India–AI Impact Summit 2026.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने India–AI Impact Summit 2026 में FiMI (फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया) लॉन्च किया।
- FiMI is a domain-specific language model built specifically for India's payments ecosystem.
- FiMI एक डोमेन-विशिष्ट भाषा मॉडल है, जिसे भारत की भुगतान प्रणाली के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है।
- Developed in-house by NPCI, it addresses limitations of general-purpose LLMs in high-scale, high-trust payment workflows.
- इसे NPCI ने इन-हाउस विकसित किया है और यह सामान्य LLMs की सीमाओं को दूर करता है, खासकर उच्च-स्तरीय और भरोसेमंद भुगतान प्रक्रियाओं में।
- FiMI currently powers NPCI's UPI Help Assistant, an AI-powered conversational support system for UPI users.
- FiMI वर्तमान में NPCI के UPI हेल्प असिस्टेंट को संचालित करता है, जो UPI उपयोगकर्ताओं के लिए AI आधारित संवादात्मक सहायता प्रणाली है।
- It supports transaction dispute handling, mandate lifecycle management, and regulatory queries.
- यह लेन-देन विवाद समाधान, मंडेट प्रबंधन और नियामकीय प्रश्नों का समाधान

करता है।

- The assistant currently supports English, Hindi, Telugu, and Bengali.
- यह असिस्टेंट वर्तमान में अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु और बंगाली भाषाओं का समर्थन करता है।
- Additional Indian languages will be added in the next 6–8 months to improve accessibility.
- अगले 6–8 महीनों में अन्य भारतीय भाषाएँ भी जोड़ी जाएंगी ताकि पहुंच बढ़ाई जा सके।

Ques: Which entity received RBI approval to acquire up to 9.95% stake in eight Indian banks?

किस संस्था को आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली?

- A) HDFC Asset Management Company / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- B) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- C) ICICI Prudential Asset Management Company / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- D) Axis Asset Management Company / एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- E) Kotak Mahindra Asset Management Company / कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Prudential Asset Management Company, along with group entities of ICICI Bank, received approval from the Reserve Bank of India to acquire up to 9.95% of the paid-up share capital or voting rights in eight Indian banks.
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक समूह की इकाइयों के साथ आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक चुकता शेयर पूंजी या मतदान

अधिकार प्राप्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।

- The banks covered under this approval are Bandhan Bank, City Union Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, HDFC Bank, Karur Vysya Bank, and RBL Bank.
- इस मंजूरी के तहत बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और RBL बैंक शामिल हैं।
- The approval is valid for one year and requires completion of major shareholding within this period.
- यह मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध है और इस अवधि में प्रमुख हिस्सेदारी पूरी करनी होगी।
- The aggregate holding must remain below 9.95% at all times.
- कुल हिस्सेदारी हर समय 9.95% से कम रखनी होगी।
- If the stake falls below 5% and is later increased again, fresh approval from RBI will be mandatory.
- यदि हिस्सेदारी 5% से नीचे गिरती है और बाद में फिर बढ़ाई जाती है, तो RBI से नई मंजूरी लेना अनिवार्य होगा

Ques: What is the minimum FD amount required to obtain IDFC First Bank's Hello Cashback Credit Card?

IDFC फर्स्ट बैंक के हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम FD राशि कितनी है?

- A) ₹5,000
- B) ₹10,000
- C) ₹15,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank has launched the Hello Cashback Credit Card, an FD-backed credit card.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो FD-आधारित

क्रेडिट कार्ड है।

- The card is aimed at first-time users and customers with no credit history.
- यह कार्ड पहली बार क्रेडिट लेने वाले और बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों के लिए बनाया गया है।
- Customers need to open a minimum FD of ₹10,000 to get the card.
- ग्राहकों को कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम ₹10,000 की FD खोलनी होगी।
- The credit limit is 100% of the FD amount.
- क्रेडिट लिमिट FD राशि का 100% होगी।
- The card is issued on the RuPay network.
- यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर जारी किया गया है।
- Founded: October 2015 | Headquarters: Mumbai | CEO: V. Vaidyanathan.
- स्थापना: अक्टूबर 2015 | मुख्यालय: मुंबई | सीईओ: वी. वैद्यनाथन।

Ques: What was India's factory-gate inflation (Wholesale Price Index – WPI) in January 2026, as per data released by the Ministry of Commerce and Industry?

जनवरी 2026 में भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई (थोक मूल्य सूचकांक – WPI) कितनी रही, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया?

- A) 0.95%
- B) 1.25%
- C) 1.81%
- D) 2.40%
- E) 3.20%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's factory-gate inflation, measured by the Wholesale Price Index (WPI), rose to 1.81% in January 2026, marking a 10-month high.
- भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई, जिसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से मापा जाता है, जनवरी 2026 में बढ़कर 1.81% हो गई, जो 10 महीनों का उच्चतम स्तर है।

- The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
- यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
- The rise in WPI inflation was mainly driven by:
 - Pickup in food prices
 - Sharp increase in core inflation
- WPI में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में तेजी और कोर महंगाई में तीव्र बढ़ोतरी रही।
- Food inflation increased to 1.4% in January 2026, after remaining flat on a year-on-year basis in December 2025.
- खाद्य महंगाई दिसंबर 2025 में स्थिर रहने के बाद जनवरी 2026 में बढ़कर 1.4% हो गई।
- Core inflation (excluding food and fuel) rose sharply to 3.2% in January 2026.
- कोर महंगाई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) जनवरी 2026 में तेजी से बढ़कर 3.2% हो गई।
- The current WPI base year is 2011–12, and the upcoming GDP series with base year 2022–23 will continue to use the existing WPI as deflators.
- वर्तमान WPI का आधार वर्ष 2011–12 है और आगामी 2022–23 आधार वर्ष वाली GDP श्रृंखला में भी WPI को डिफ्लेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

Ques: Which company signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Rajasthan Gramin Bank to establish a strategic vehicle financing partnership? किस कंपनी ने राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ रणनीतिक वाहन वित्तपोषण साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Ashok Leyland / अशोक लेलैंड
- B) Tata Motors / टाटा मोटर्स
- C) Mahindra & Mahindra / महिंद्रा एंड महिंद्रा
- D) Eicher Motors / आइशर मोटर्स
- E) Force Motors / फोर्स मोटर्स

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Ashok Leyland, the flagship company of the Hinduja Group, signed an MoU with Rajasthan Gramin Bank to establish a strategic vehicle financing partnership.
- हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने रणनीतिक वाहन वित्तपोषण साझेदारी के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- Rajasthan Gramin Bank is the largest bank in Rajasthan in terms of branch network.
- शाखा नेटवर्क के लिहाज से राजस्थान ग्रामीण बैंक, राजस्थान का सबसे बड़ा बैंक है।
- The partnership aims to provide end-to-end financial solutions for Ashok Leyland customers.
- इस साझेदारी का उद्देश्य अशोक लेलैंड के ग्राहकों को एंड-टू-एंड वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना है।
- Customers will get access to customised vehicle loan products and flexible repayment options.
- ग्राहकों को अनुकूलित वाहन ऋण उत्पाद और लचीले पुनर्भुगतान विकल्प उपलब्ध होंगे।
- Financing solutions will be tailored according to individual customer needs.
- वित्तपोषण समाधान ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

Ques: To what percentage has LIC increased its stake in Cipla recently?
हाल ही में LIC ने सिप्ला में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है?

- A) 7%
- B) 8%
- C) 9%
- D) 10%
- E) 12%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Life Insurance Corporation of India (LIC) increased its holding in Cipla from 7% to 9% in less than three months.
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सिप्ला में अपनी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 9% कर दी, वह भी तीन महीने से कम समय में।
- LIC acquired over 1.64 crore shares through open market purchases between November 27 and February 18.
- LIC ने 27 नवंबर से 18 फरवरी के बीच खुले बाजार से 1.64 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे।
- Earlier, LIC had increased its stake from 5.025% to 7.055% over four months till November last year.
- इससे पहले, LIC ने पिछले वर्ष नवंबर तक चार महीनों में अपनी हिस्सेदारी 5.025% से बढ़ाकर 7.055% की थी।
- LIC is India's largest institutional investor.
- LIC भारत का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है।

Ques: Indian Overseas Bank (IOB) signed an MoU with which institution to design and deliver customised training programmes for its senior leadership and executives?

इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने अपने वरिष्ठ नेतृत्व और अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और संचालित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Indian Institute of Management Ahmedabad – Indian Institute of Management Ahmedabad / भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
- B) Indian Institute of Management Bangalore – Indian Institute of Management Bangalore / भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर
- C) Indian Institute of Management Kozhikode – Indian Institute of Management Kozhikode / भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड
- D) Indian Institute of Management Calcutta – Indian Institute of Management

Calcutta / भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता

E) Indian Institute of Management Lucknow – Indian Institute of Management Lucknow / भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Indian Overseas Bank signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Indian Institute of Management Kozhikode (IIM-K), Kerala.
- इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने केरल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड (IIM-K) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU aims to foster collaboration in designing, delivering, and certifying customised training programmes and workshops for IOB's senior leadership and executives.
- इस MoU का उद्देश्य IOB के वरिष्ठ नेतृत्व और अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के डिजाइन, संचालन और प्रमाणन में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- The agreement was signed as part of the 90th Foundation Day (February 10) celebrations of Indian Overseas Bank.
- यह समझौता इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 90वें स्थापना दिवस (10 फरवरी) समारोह के अवसर पर किया गया।
- IOB also announced the establishment of a dedicated Centre of Excellence (CoE) for training and capacity building.
- IOB ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence - CoE) स्थापित करने की भी घोषणा की।

About Indian Overseas Bank

- Established : 1937
- HQ : Chennai
- MD & CEO : Shri Ajay Kumar Srivastava
- Tagline : Good People to Grow With

Ques: Which body has issued a discussion paper proposing reforms to strengthen transparency and procedural discipline under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक अनुशासन को मजबूत करने के लिए सुधार प्रस्तावित करते हुए चर्चा पत्र किस निकाय ने जारी किया है?

- A) Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) / दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया
- B) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- C) Ministry of Corporate Affairs (MCA) / कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
- D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
- E) National Company Law Tribunal (NCLT) / राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has issued a discussion paper to strengthen transparency, accountability, and procedural discipline under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).
- दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने IBC के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रक्रियात्मक अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया है।
- The proposals aim to improve the functioning and accountability of the Committee of Creditors (CoC) during the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP).
- इन प्रस्तावों का उद्देश्य कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान लेनदारों की समिति (CoC) की कार्यप्रणाली और जवाबदेही में सुधार करना है।
- Key proposals include mandatory recording of recovery expectations, assessment of resolution applicants, and submission of a Going Concern

Assessment Report in the first CoC meeting.

- प्रमुख प्रस्तावों में अपेक्षित वसूली का रिकॉर्ड, समाधान आवेदकों का मूल्यांकन और पहली CoC बैठक में गोइंग कंसर्न असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।
- IBBI has also proposed stricter handling of delayed claims and changes in participation rules for operational creditors.
- IBBI ने विलंबित दावों के सख्त निपटान और परिचालन लेनदारों की भागीदारी से जुड़े नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है।
- IBBI was established on 1 October 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, with its headquarters in New Delhi, and functions under the Ministry of Corporate Affairs.
- IBBI की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

Ques: From which year will India start receiving detailed transaction data from overseas crypto platforms under a global reporting framework?

वैश्विक रिपोर्टिंग ढांचे के तहत भारत किस वर्ष से विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से विस्तृत लेनदेन डेटा प्राप्त करना शुरू करेगा?

- A) 2025
- B) 2026
- C) 2027
- D) 2028
- E) 2029

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- From April 2027, a global reporting regime will require foreign crypto platforms to share detailed transaction data with India.
- अप्रैल 2027 से एक वैश्विक रिपोर्टिंग व्यवस्था के तहत विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को

भारत के साथ विस्तृत लेनदेन डेटा साझा करना अनिवार्य होगा।

- This move ends the era of offshore opacity and strengthens tax, compliance, and data-sharing norms for exchanges and investors.

- यह कदम विदेशी गोपनीयता (offshore opacity) के दौर को समाप्त करेगा और एक्सचेंज व निवेशकों के लिए कर, अनुपालन एवं डेटा-साझाकरण मानकों को सख्त करेगा।

- It is aligned with the OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), a global information-sharing mechanism.

- यह OECD के Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) के अनुरूप है, जो एक वैश्विक सूचना-साझाकरण तंत्र है।

- Cross-border exchange of crypto data will begin from April 1, 2027, enabling tax authorities to track offshore trades of Indian users.

- क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो डेटा का आदान-प्रदान 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा, जिससे कर प्राधिकरण भारतीय उपयोगकर्ताओं के विदेशी ट्रेड को ट्रैक कर सकेंगे।

- Existing tax rules will continue: 30% tax on crypto profits and 1% TDS on transactions.

- मौजूदा कर नियम लागू रहेंगे: क्रिप्टो लाभ पर 30% कर और लेनदेन पर 1% TDS।

Ques: Which company has launched “Cashfree Here”, a payments extension enabling UPI and biometric card payments directly within AI chat applications?

किस कंपनी ने “Cashfree Here” लॉन्च किया है, जो AI चैट एप्लिकेशनों के भीतर सीधे UPI और बायोमेट्रिक कार्ड भुगतान को सक्षम बनाता है?

A) Cashfree Payments / कैशफ्री पेमेंट्स

B) Paytm / पेटीएम

C) PhonePe / फोनपे

D) Razorpay / रेज़रपे

E) Pine Labs / पाइन लैब्स

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Cashfree Payments has launched “Cashfree Here”, a payments extension that allows UPI and passkey-based biometric card payments directly within AI chat applications such as ChatGPT and Claude.
- कैशफ्री पेमेंट्स ने “Cashfree Here” लॉन्च किया है, जो ChatGPT और Claude जैसे AI चैट एप्लिकेशनों के भीतर सीधे UPI और पासकी-आधारित बायोमेट्रिक कार्ड भुगतान की सुविधा देता है।
- The solution was unveiled at the India AI Impact Summit 2026 in collaboration with Mastercard and Swiggy.
- यह समाधान इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मास्टरकार्ड और स्विगी के सहयोग से पेश किया गया।
- Cashfree Here embeds a native payments layer inside conversational AI interfaces, enabling users to complete transactions without leaving the chat window.
- Cashfree Here संवादात्मक AI इंटरफेस के भीतर एक नेटिव पेमेंट लेयर जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ता चैट छोड़े बिना भुगतान कर सकते हैं।
- It supports UPI payments and card payments using passkey-enabled biometric authentication, reducing dependence on OTP-based verification.
- यह UPI भुगतान और पासकी-सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए कार्ड भुगतान को सपोर्ट करता है, जिससे OTP पर निर्भरता कम होती है।
- Key features include in-chat checkout via OpenAI Apps SDK and Anthropic MCP apps, PCI-compliant secure processing, and reduced checkout friction.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में इन-चैट चेकआउट, PCI-अनुपालक सुरक्षित प्रोसेसिंग और तेज़ व सरल भुगतान प्रक्रिया शामिल है।

Ques: Indian Overseas Bank has simplified the death claim settlement procedure for claims up to what amount?

इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया को किस राशि तक के दावों के लिए सरल बनाया है?

- A) ₹5 lakh
- B) ₹10 lakh
- C) ₹12 lakh
- D) ₹15 lakh
- E) ₹20 lakh

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- **Indian Overseas Bank (IOB)** has launched an Online Death Claim Settlement Portal.
- इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल शुरू किया है।
- The initiative aims to provide a simplified, transparent, and time-bound solution for families and legal heirs.
- इस पहल का उद्देश्य परिवारों और कानूनी वारिसों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान प्रदान करना है।
- To reduce stress for grieving families, IOB has introduced a simplified procedure for claims up to ₹15 lakh.
- शोकाकुल परिवारों का तनाव कम करने के लिए ₹15 लाख तक के दावों के लिए सरल प्रक्रिया लागू की गई है।
- The bank has committed to processing such claims within 15 days.
- बैंक ने ऐसे दावों को 15 दिनों के भीतर निपटाने की प्रतिबद्धता जताई है।

About Indian Overseas Bank :

- Established : 1937
- HQ : Chennai
- MD & CEO : Shri Ajay Kumar Srivastava
- Tagline : Good People to Grow With

Ques: Airtel Money has received a Certificate of Registration (CoR) from the RBI to operate under which category of NBFC?

एयरटेल मनी को RBI से किस श्रेणी की NBFC के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त हुआ है?

- A) Type I Deposit Accepting NBFC / टाइप I जमा स्वीकार करने वाली NBFC
- B) Core Investment Company / कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी
- C) Infrastructure Finance NBFC / अवसंरचना वित्त NBFC
- D) Housing Finance Company / हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
- E) Type II Non-Deposit Accepting NBFC / टाइप II गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Airtel Money, a subsidiary of Bharti Airtel, has received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India to operate as a Type II, non-deposit accepting NBFC.
- एयरटेल मनी, जो भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है, को भारतीय रिज़र्व बैंक से टाइप II गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
- A Type II NBFC is permitted to undertake specified financial activities as allowed under RBI regulations.
- टाइप II NBFC को RBI के नियमों के अनुसार निर्धारित वित्तीय गतिविधियाँ करने की अनुमति होती है।
- Such NBFCs are not allowed to accept public deposits.
- इस प्रकार की NBFC जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती।
- These entities function under the regulatory supervision of the RBI.
- ऐसी संस्थाएँ RBI की नियामक निगरानी में कार्य करती हैं।

Ques: RBI's newly built high-security data centre is located in which city?
RBI का नया उच्च-सुरक्षा डेटा सेंटर किस शहर में स्थित है?

- A) Hyderabad / हैदराबाद
- B) Chennai / चेन्नई
- C) Bhubaneswar / भुवनेश्वर
- D) Pune / पुणे
- E) Ahmedabad / अहमदाबाद

Answer: C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has built a high-security data centre in Bhubaneswar, Odisha.
- Reserve Bank of India (RBI) ने भुवनेश्वर, ओडिशा में उच्च-सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया है।
- The move aims to secure critical financial data and keep records away from cross-border threat zones and high seismic-risk regions.
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना और रिकॉर्ड को सीमा-पार खतरों व उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रखना है।
- The greenfield facility will house core computing systems supporting currency management, payment & settlement systems, and regulatory data functions.
- यह ग्रीनफील्ड सुविधा मुद्रा प्रबंधन, भुगतान एवं निपटान प्रणाली और नियामकीय डेटा कार्यों के लिए कोर कंप्यूटिंग सिस्टम को होस्ट करेगी।
- This is RBI's second data centre.
- यह RBI का दूसरा डेटा सेंटर है।
- RBI's Primary Data Centre is located in Kharghar, Navi Mumbai.
- RBI का प्राथमिक डेटा सेंटर खारघर, नवी मुंबई में स्थित है।

Ques: Which department released the report titled “Socio-Economic Impact Analysis of the Incentive Scheme for Promotion of RuPay Debit Card and low-value BHIM-UPI Transactions (P2M)”?

“रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई (P2M) लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण” शीर्षक रिपोर्ट किस विभाग द्वारा जारी की गई?

- A) Department of Economic Affairs / आर्थिक कार्य विभाग
- B) Department of Financial Services / वित्तीय सेवाएं विभाग
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- E) Ministry of Electronics and IT / इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The report was released by the Department of Financial Services under the Ministry of Finance.
- यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी की गई।
- Between 2021 and 2025, digital transactions increased nearly 11 times, with Unified Payments Interface (UPI) accounting for about 80% of total digital payments in India.
- 2021 से 2025 के बीच डिजिटल लेनदेन लगभग 11 गुना बढ़े, जिसमें UPI का हिस्सा लगभग 80% रहा।
- The Government provided ₹8,276 crore to banks and fintech companies to promote affordable digital payments.
- सरकार ने डिजिटल भुगतान को सुलभ और किफायती बनाए रखने हेतु बैंकों और फिनटेक कंपनियों को ₹8,276 करोड़ प्रदान किए।
- Annual Incentive Breakdown: FY22 – ₹1,389 crore; FY23 – ₹2,210 crore; FY24 – ₹3,631 crore; FY25 – ₹1,046 crore.
- वार्षिक विवरण: वित्त वर्ष 2022 – ₹1,389 करोड़; 2023 – ₹2,210 करोड़; 2024 – ₹3,631 करोड़; 2025 – ₹1,046 करोड़।

- The survey covered 10,378 respondents across 15 states, including users, merchants, and service providers.
- सर्वेक्षण में 15 राज्यों के 10,378 उत्तरदाताओं (उपयोगकर्ता, व्यापारी और सेवा प्रदाता) को शामिल किया गया।
- 57% of users prefer UPI over cash (38%), and 66% of users aged 18–25 follow digital-first habits.
- 57% उपयोगकर्ता UPI को नकद (38%) से अधिक पसंद करते हैं, जबकि 18–25 आयु वर्ग के 66% उपयोगकर्ता डिजिटल-प्रथम आदतें अपनाते हैं।
- 94% of small merchants accept UPI, and 57% reported increased sales due to digital adoption.
- 94% छोटे व्यापारी UPI स्वीकार करते हैं, और 57% ने डिजिटल अपनाने से बिक्री में वृद्धि की सूचना दी।
- 74% users cited speed as the main benefit, while 52% were motivated by cashback incentives.
- 74% उपयोगकर्ताओं ने “गति” को मुख्य लाभ बताया, जबकि 52% कैशबैक प्रोत्साहन से प्रेरित थे।

Growth (2021–2025) | वृद्धि (2021–2025):

- Transaction volume increased nearly 11-fold.
- लेनदेन मात्रा लगभग 11 गुना बढ़ी।
- UPI QR deployment grew from 9.3 crore to around 65.8 crore terminals.
- UPI QR तैनाती 9.3 करोड़ से बढ़कर लगभग 65.8 करोड़ टर्मिनलों तक पहुंची।
- Banks on the UPI platform increased from 216 to 661.
- UPI प्लेटफॉर्म पर बैंकों की संख्या 216 से बढ़कर 661 हो गई।
- Third-party fintech app providers increased from 16 to 38.
- थर्ड-पार्टी फिनटेक ऐप प्रदाताओं की संख्या 16 से बढ़कर 38 हो गई।

Ques: ASK Asset & Wealth Management Group has received SEBI approval to operate as what in India's Mutual Fund business?

ASK एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप को सेबी से भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय में किस रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है?

- A) Investment Manager / निवेश प्रबंधक
- B) Registrar & Transfer Agent / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट
- C) Custodian / कस्टोडियन
- D) Portfolio Auditor / पोर्टफोलियो ऑडिटर
- E) Clearing Member / क्लियरिंग सदस्य

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- ASK Asset & Wealth Management Group received regulatory approval from Securities and Exchange Board of India (SEBI) to start operations as an Investment Manager for the Mutual Fund (MF) business in India.
- ASK एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से भारत में म्यूचुअल फंड (MF) व्यवसाय के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में संचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है।
- With this approval, it becomes the 52nd fund house in India's Mutual Fund industry.
- इस मंजूरी के साथ यह भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग की 52वीं फंड हाउस बन गई है।
- The Mutual Fund industry recorded Assets Under Management (AUM) of ₹81 lakh crore as of January 31, 2026.
- 31 जनवरी 2026 तक म्यूचुअल फंड उद्योग का प्रबंधित परिसंपत्ति (AUM) ₹81 लाख करोड़ दर्ज किया गया।

Ques: Axis Bank has partnered with which airline to launch co-branded travel and lifestyle credit cards?

एक्सिस बैंक ने सह-ब्रांडेड ट्रैवल एवं लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने हेतु किस एयरलाइन के साथ साझेदारी की है?

- A) Air India / एयर इंडिया

- B) SpiceJet / स्पाइसजेट
- C) Vistara / विस्तारा
- D) IndiGo / इंडिगो
- E) Akasa Air / आकाशा एयर

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या :

- Axis Bank, India's third-largest private sector bank, has partnered with IndiGo (InterGlobe Aviation Limited) to launch two co-branded credit cards.
- भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड) के साथ मिलकर दो सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं।
- The two cards are: IndiGo Axis Bank Credit Card and IndiGo Axis Bank Premium Credit Card.
- दोनों कार्ड हैं: इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड।
- The cards offer rewards through IndiGo's loyalty programme IndiGo BluChip.
- ये कार्ड इंडिगो के लॉयल्टी प्रोग्राम "IndiGo BluChip" के माध्यम से रिवॉर्ड प्रदान करते हैं।
- IndiGo Axis Bank Credit Card has an annual fee of ₹799 (including GST) and targets retail customers.
- इंडिगो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की वार्षिक शुल्क ₹799 (GST सहित) है और यह रिटेल ग्राहकों के लिए है।
- IndiGo Axis Bank Premium Credit Card has an annual fee of ₹5,000 (including GST) and is designed for affluent and frequent travellers.
- इंडिगो एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की वार्षिक शुल्क ₹5,000 (GST सहित) है और यह समृद्ध एवं नियमित यात्रियों के लिए है।
- Both cards are available on RuPay Network and Visa Network.
- दोनों कार्ड RuPay नेटवर्क और Visa नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।

Ques : What is the total asset monetisation target under NMP 2.0 for FY26–FY30?

FY26–FY30 के लिए NMP 2.0 के तहत कुल परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य कितना है?

- A) ₹10 lakh crore / ₹10 लाख करोड़
- B) ₹6 lakh crore / ₹6 लाख करोड़
- C) ₹12 lakh crore / ₹12 लाख करोड़
- D) ₹16.72 lakh crore / ₹16.72 लाख करोड़
- E) ₹20 lakh crore / ₹20 लाख करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Government has launched the National Monetisation Pipeline (NMP) 2.0 to monetise assets worth ₹16.72 lakh crore during FY26–FY30.
- सरकार ने FY26–FY30 के दौरान ₹16.72 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए National Monetisation Pipeline (NMP) 2.0 लॉन्च किया है।
- The programme was launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- इस कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने किया।
- NMP 2.0 is more than 2.6 times larger than NMP 1.0 and includes a ₹5.8 lakh crore private sector investment component.
- NMP 2.0, NMP 1.0 से 2.6 गुना बड़ा है और इसमें ₹5.8 लाख करोड़ का निजी क्षेत्र निवेश घटक शामिल है।
- Major sectors covered include Highways, MMLPs & Ropeways (₹4.42 lakh crore), Power (₹2.76 lakh crore), Ports (₹2.63 lakh crore), Railways (₹2.62 lakh crore), and Coal (₹2.16 lakh crore).
- प्रमुख क्षेत्रों में राजमार्ग, MMLPs एवं रोपवे (₹4.42 लाख करोड़), बिजली (₹2.76 लाख करोड़), बंदरगाह (₹2.63 लाख करोड़), रेलवे (₹2.62 लाख करोड़) और कोयला (₹2.16 लाख करोड़) शामिल हैं।
- The proceeds from monetisation will be used for capital expenditure and new infrastructure creation, and revenues from central projects will flow to the Consolidated Fund of India.

- मुद्रिकरण से प्राप्त राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय और नई अवसंरचना निर्माण में किया जाएगा, तथा केंद्रीय परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व भारत की समेकित निधि में जाएगा।

Ques: Which digital payments platform has introduced biometric authentication for UPI transactions up to ₹5,000?

किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने ₹5,000 तक के UPI लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की है?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) Google Pay / गूगल पे
- C) BHIM / भीम
- D) Amazon Pay / अमेज़न पे
- E) PhonePe / फोनपे

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या :

- PhonePe has introduced biometric authentication for Unified Payments Interface (UPI) transactions.
- फोनपे ने यूनियाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की है।
- Users can authorise payments using fingerprint authentication or facial recognition within the app.
- उपयोगकर्ता ऐप के भीतर फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के माध्यम से भुगतान को अधिकृत कर सकते हैं।
- Biometric authentication is applicable for UPI payments up to ₹5,000.
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ₹5,000 तक के UPI भुगतान पर लागू होगा।
- Transactions above ₹5,000 will continue to require the UPI PIN as per regulatory guidelines.

- ₹5,000 से अधिक के लेनदेन के लिए नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार UPI पिन आवश्यक रहेगा।
- The feature uses the smartphone's native device-level security system and acts as a second authentication factor, ensuring faster and secure payment authorisation.
- यह सुविधा स्मार्टफोन की डिवाइस-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है और द्वितीय प्रमाणीकरण कारक के रूप में कार्य करती है, जिससे भुगतान अधिक तेज़ और सुरक्षित होता है।
- The objective is to reduce friction in digital payments, improve user convenience, and strengthen transaction security through hardware-grade authentication.
- इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना, उपयोगकर्ता सुविधा बढ़ाना तथा हार्डवेयर-ग्रेड प्रमाणीकरण के माध्यम से लेनदेन सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

Ques: Which organisation provided a USD 197.67 million guarantee to Citibank N.A. for supporting rooftop solar projects in India?

भारत में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के समर्थन हेतु Citibank N.A. को 197.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी किस संगठन ने प्रदान की?

- A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) / बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
- D) International Finance Corporation (IFC) / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: C

Explanation | व्याख्या:

- A guarantee of USD 197.67 million was provided to Citibank N.A..

- 197.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी Citibank N.A. को प्रदान की गई।
- The guarantee was given by the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), the guarantee arm of the World Bank Group (WBG).
- यह गारंटी Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) द्वारा प्रदान की गई, जो World Bank Group (WBG) की गारंटी शाखा है।
- The tenure of the guarantee is five years.
- इस गारंटी की अवधि पाँच वर्ष है।
- The objective is to support Citibank's non-shareholder loan to the State Bank of India (SBI).
- इसका उद्देश्य State Bank of India (SBI) को Citibank द्वारा दिए गए गैर-शेयरधारक ऋण का समर्थन करना है।
- The loan will help refinance investments in India's grid-connected Rooftop Solar Photovoltaic (GRPV) systems.
- यह ऋण भारत की ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक (GRPV) प्रणालियों में निवेश के पुनर्वित्त (refinancing) का समर्थन करेगा।

Ques: An EPF account is declared inoperative if there is no contribution for how many consecutive months?

कितने लगातार महीनों तक अंशदान न होने पर EPF खाता निष्क्रिय घोषित किया जाता है?

- A) 12 months / 12 महीने
- B) 24 months / 24 महीने
- C) 30 months / 30 महीने
- D) 36 months / 36 महीने
- E) 48 months / 48 महीने

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Ministry of Labour and Employment will auto credit ₹30.52 crore lying in 7.11 lakh inoperative EPFO accounts.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 7.11 लाख निष्क्रिय EPFO खातों में पड़ी ₹30.52 करोड़ राशि स्वतः जमा करेगा।
- These accounts hold ₹1,000 or less per account.
- इन खातों में प्रति खाता ₹1,000 या उससे कम राशि है।
- No documentation is required; only bank verification and Aadhaar-seeded account confirmation are needed.
- किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं; केवल बैंक सत्यापन और आधार-सीडेड खाते की पुष्टि आवश्यक है।
- Total inoperative EPFO accounts stand at 31.86 lakh, holding ₹10,903 crore.
- कुल 31.86 लाख निष्क्रिय EPFO खाते हैं, जिनमें ₹10,903 करोड़ जमा हैं।
- As per Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) rules, an EPF account is declared 'inoperative' if no contribution is received for 36 consecutive months.
- ईपीएफओ नियमों के अनुसार, यदि किसी EPF खाते में लगातार 36 महीनों तक कोई अंशदान नहीं होता, तो उसे 'निष्क्रिय' घोषित किया जाता है।
- The move aims to benefit small subscribers and simplify fund access.
- यह कदम छोटे खाताधारकों को लाभ पहुंचाने और धन निकासी को सरल बनाने के उद्देश्य से है।

Ques : Which bank organised a Facilitation Camp under the Salary Account Package for Central Government Employees?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत सुविधा शिविर किस बैंक ने आयोजित किया?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) organised a Facilitation Camp under its Salary Account Package for Central Government Employees.
- Punjab National Bank (PNB) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत एक सुविधा शिविर आयोजित किया।
- The package offers a one-stop financial solution including banking services, debit & credit card benefits, and insurance protection.
- यह पैकेज बैंकिंग सेवाएं, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड लाभ तथा बीमा सुरक्षा सहित एक समग्र वित्तीय समाधान प्रदान करता है।

Insurance Coverage | बीमा कवरेज:

- Personal Accident Insurance (PAI): up to ₹1.5 crore
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI): ₹1.5 करोड़ तक
- Air Accident Insurance (AAI): up to ₹2 crore
- हवाई दुर्घटना बीमा (AAI): ₹2 करोड़ तक
- Permanent Disability Cover (TPD/PPD): up to ₹1.5 crore
- स्थायी विकलांगता कवर (TPD/PPD): ₹1.5 करोड़ तक
- Life Insurance: up to ₹20 lakh (with optional top-up)
- जीवन बीमा: ₹20 लाख तक (वैकल्पिक टॉप-अप के साथ)
- Comprehensive medical insurance for self & family
- स्वयं और परिवार के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा

Ques: Which firm has been appointed by IDFC First Bank to investigate the ₹590 crore fraud?

₹590 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किस फर्म को नियुक्त किया है?

A) Deloitte / डेलॉइट

- B) EY / अन्स्टै एंड यंग (EY)
- C) PwC / प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC)
- D) KPMG / केपीएमजी
- E) Grant Thornton / ग्रॉंट थॉर्नटन

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- IDFC First Bank has appointed KPMG as a forensic auditor to investigate a ₹590 crore fraud at its Chandigarh branch.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ शाखा में हुए ₹590 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए केपीएमजी को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है।
- The fraud involved Haryana government accounts and suspected collusion between branch staff and external parties.
- यह धोखाधड़ी हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी थी और शाखा कर्मचारियों व बाहरी पक्षों की मिलीभगत की आशंका है।
- Funds were allegedly diverted from a State government deposit account to external beneficiaries.
- राज्य सरकार के जमा खाते से धनराशि कथित रूप से बाहरी लाभार्थियों को स्थानांतरित की गई।
- Forged cheques and irregular entries were reportedly cleared by branch employees.
- जाली चेक और अनियमित एंट्री शाखा कर्मचारियों द्वारा क्लियर किए गए।
- The Haryana government has withdrawn around ₹200 crore deposits and de-pannelled the bank from State business.
- हरियाणा सरकार ने लगभग ₹200 करोड़ की जमा राशि वापस ले ली और बैंक को राज्य के कार्यों से हटा दिया।
- The bank's stock plunged nearly 20% intraday after the fraud surfaced.
- घोटाले के सामने आने के बाद बैंक के शेयर में लगभग 20% की गिरावट दर्ज की गई।
- Reserve Bank of India (RBI) Governor stated that the issue does not pose systemic risk to the banking system.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने कहा कि यह मामला बैंकिंग प्रणाली के लिए

प्रणालीगत जोखिम नहीं है।

- The bank plans to implement AI-based verification for large-ticket transactions going forward.
- बैंक आगे बड़े लेनदेन के लिए AI-आधारित सत्यापन प्रणाली अपनाएगा।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has released draft directions permitting Authorised Dealer (AD) Category-I banks to undertake which type of derivative contracts?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अधिकृत डीलर (AD) श्रेणी-I बैंकों को किस प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति देने हेतु मसौदा निर्देश जारी किए हैं?

- A) Currency Swaps / करेंसी स्वैप
- B) Interest Rate Futures / ब्याज दर वायदा
- C) Non-Deliverable Derivative Contracts / नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट
- D) Credit Default Swaps / क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
- E) Commodity Futures / कमोडिटी वायदा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has issued draft directions allowing AD Category-I banks to undertake Rupee Non-Deliverable Derivative Contracts (NDDCs).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने AD श्रेणी-I बैंकों को रुपये में नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (NDDCs) करने की अनुमति देने हेतु मसौदा निर्देश जारी किए हैं।
- The move is expected to strengthen banking operations in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) located in the Gandhinagar–Ahmedabad Metropolitan Region.
- यह कदम गांधीनगर–अहमदाबाद महानगरीय क्षेत्र में स्थित GIFT सिटी में बैंकिंग संचालन को सुदृढ़ करेगा।

What are NDDCs? / NDDCs क्या हैं?

- Non-Deliverable Derivative Contracts are forex derivative instruments where no physical exchange of currency takes place.
- नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसे विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव साधन हैं, जिनमें मुद्रा का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं होता।
- Settlement is done in cash, usually in rupees or foreign currency.
- इनका निपटान नकद में, सामान्यतः रुपये या विदेशी मुद्रा में किया जाता है।
- They are widely used by global investors to hedge currency risk.
- इन्हें वैश्विक निवेशकों द्वारा मुद्रा जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

Key Proposals in RBI Draft Framework / RBI मसौदा ढांचे के प्रमुख प्रावधान:

- Eligible participants include other AD banks, overseas entities, IFSC Banking Units (IBUs), and Offshore Banking Units (OBUs).
 - पात्र प्रतिभागियों में अन्य AD बैंक, विदेशी संस्थाएँ, IFSC बैंकिंग इकाइयाँ (IBUs) तथा ऑफशोर बैंकिंग इकाइयाँ (OBUs) शामिल हैं।
 - Transactions may be undertaken directly or through overseas branches on a back-to-back basis.
 - लेन-देन सीधे या विदेशी शाखाओं के माध्यम से बैंक-टू-बैंक आधार पर किए जा सकते हैं।
 - The framework also includes provisions related to IFSC presence, offshore electronic trading platforms (ETPs), liberalisation of forex operations, and deployment of surplus foreign currency funds.
 - इस ढांचे में IFSC उपस्थिति से संबंधित शर्तें, ऑफशोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETPs), विदेशी मुद्रा परिचालन के उदारीकरण तथा अधिशेष विदेशी मुद्रा निधियों के उपयोग से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
-

Ques: The first-phase Agri Robotics Laboratory inaugurated by SBI has been established in which state?

एसबीआई द्वारा उद्घाटित प्रथम चरण का एग्री रोबोटिक्स लैब किस राज्य में स्थापित किया गया है?

- A) Karnataka / कर्नाटक
- B) Telangana / तेलंगाना
- C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Punjab / पंजाब

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) Chairman Challa Sreenivasulu Setty inaugurated the first-phase Agri Robotics Lab.
- एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी ने प्रथम चरण के एग्री रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया।
- The lab has been established at Professor Jayashankar Telangana Agricultural University (PJTSAU), located in Telangana.
- यह लैब तेलंगाना स्थित प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) में स्थापित की गई है।
- The project is funded by SBI Foundation, the CSR arm of SBI.
- इसे एसबीआई फाउंडेशन (एसबीआई की CSR शाखा) द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- The initiative promotes the use of AI, drones, robotics, and unmanned tractors in agriculture.
- यह पहल कृषि में एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और बिना चालक ट्रैक्टर के उपयोग को बढ़ावा देती है।

Ques: ESIC was established in which year?

ईएसआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

- A) 1948 / 1948
- B) 1950 / 1950
- C) 1952 / 1952
- D) 1955 / 1955
- E) 1960 / 1960

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Employees' State Insurance Corporation (ESIC) commenced its 75th Year of Service celebration at Bharat Mandapam, New Delhi.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में सेवा के 75वें वर्ष का उत्सव प्रारंभ किया।
- ESIC started its journey in 1952 with around 1.2 lakh beneficiaries and one dispensary.
- ईएसआईसी ने 1952 में लगभग 1.2 लाख लाभार्थियों और एक डिस्पेंसरी के साथ शुरुआत की।
- Currently, ESIC covers over 15 crore beneficiaries through a vast network of hospitals, medical colleges, and dispensaries.
- वर्तमान में ईएसआईसी 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और डिस्पेंसरी के नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है।
- Mansukh Mandaviya addressed the event and highlighted ESIC's role in strengthening social security.
- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक सुरक्षा में ईएसआईसी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

About ESIC :

- Established – 1952
- Headquarters – New Delhi
- Chairman (2026) – Dr. Mansukh Mandaviya

Ques: A penalty of ₹38.60 lakh was imposed on which bank for violations related to savings deposit interest, locker rent refunds, and SHG credit reporting?

बचत जमा पर ब्याज भुगतान, लॉकर किराया रिफंड और SHG सदस्यों की क्रेडिट रिपोर्टिंग से जुड़े उल्लंघनों के लिए ₹38.60 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) UCO Bank / यूको बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- UCO Bank has been imposed a penalty of ₹38.60 lakh.
- यूको बैंक पर ₹38.60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
- The penalty was imposed for violations related to periodic interest payment on savings deposits, locker rent refunds, and credit information reporting for Self Help Group (SHG) members.
- यह जुर्माना बचत जमा पर समय-समय पर ब्याज भुगतान, लॉकर किराया वापसी और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों की क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से जुड़े उल्लंघनों के कारण लगाया गया।
- The penalty was imposed under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.
- यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत लगाया गया।

Ques: Fitch Ratings has affirmed the long-term rating of PNB and Bank of Baroda at which level?

फिच रेटिंग्स ने PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा की दीर्घकालिक रेटिंग किस स्तर पर बरकरार रखी है?

- A) BBB+ / बीबीबी+
- B) BBB- / बीबीबी-
- C) BB+ / बीबी+
- D) A- / ए-
- E) AA- / एए-

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Fitch Ratings affirmed the long-term Issuer Default Rating (IDR) of Punjab National Bank (PNB) and Bank of Baroda (BoB) at 'BBB-' with a stable outlook.
- फिच रेटिंग्स ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की दीर्घकालिक रेटिंग 'BBB-' स्थिर दृष्टिकोण के साथ बरकरार रखी।
- The rating reflects a high probability of extraordinary government support, if required.
- यह रेटिंग आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा असाधारण समर्थन की उच्च संभावना को दर्शाती है।
- The Government of India holds about 70% stake in PNB and 64% in BoB.
- भारत सरकार की PNB में लगभग 70% और BoB में 64% हिस्सेदारी है।
- Fitch also upgraded the Viability Rating of both banks to 'BB' from 'BB-' due to improved asset quality, capitalisation and profitability.
- फिच ने बेहतर एसेट क्वालिटी, पूंजीकरण और लाभप्रदता के कारण दोनों बैंकों की वायबिलिटी रेटिंग 'BB-' से बढ़ाकर 'BB' कर दी।
- Punjab National Bank was established in 1894 and its headquarters is located in New Delhi.
- पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में

स्थित है।

- The MD & CEO (2026) of PNB is Atul Kumar Goel.
- वर्ष 2026 में PNB के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल हैं।

Ques: According to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, India's climate action spending has increased to nearly what percentage of GDP?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, भारत का जलवायु कार्रवाई व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग कितने प्रतिशत हो गया है?

- A) 5.6%
- B) 4.2%
- C) 3.7%
- D) 6.5%
- E) 7.0%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Union Finance Minister Nirmala Sitharaman stated that India has increased its climate action spending to nearly 5.6% of Gross Domestic Product (GDP), up from 3.7% six years ago.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने अपना जलवायु कार्रवाई व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 5.6 प्रतिशत कर दिया है, जो छह वर्ष पूर्व 3.7 प्रतिशत था।
- The Union Budget 2026–27 includes funding and incentives for carbon capture strategies.
- केंद्रीय बजट 2026–27 में कार्बन कैप्चर रणनीतियों के लिए वित्तपोषण और प्रोत्साहन शामिल हैं।
- A ₹20,000-crore outlay has been allocated to help businesses reduce their carbon footprint.

- व्यवसायों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता हेतु 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- The initiative aims to support India's transition towards a greener and sustainable economy.
- इस पहल का उद्देश्य भारत को हरित और सतत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है।

Ques: What is the present annual remittance limit under the Liberalised Remittance Scheme (LRS)?

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत वर्तमान वार्षिक प्रेषण सीमा क्या है?

- A) USD 25,000 / 25,000 अमेरिकी डॉलर
- B) USD 1,00,000 / 1,00,000 अमेरिकी डॉलर
- C) USD 2,50,000 / 2,50,000 अमेरिकी डॉलर
- D) USD 5,00,000 / 5,00,000 अमेरिकी डॉलर
- E) USD 6,00,000 / 6,00,000 अमेरिकी डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Outward remittances under LRS fell by 4.1% to \$21.37 billion in FY26 (April–December) from \$22.28 billion last year.
- वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल–दिसंबर) में एलआरएस के तहत विदेशी प्रेषण 4.1% घटकर 21.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 22.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- This marks the second straight year of decline in outward remittances.
- यह विदेशी प्रेषण में लगातार दूसरा वर्ष है जब गिरावट दर्ज की गई है।
- Under LRS, resident individuals can remit up to USD 2,50,000 per financial year for permissible transactions.
- एलआरएस के तहत निवासी व्यक्ति अनुमत लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष

अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर भेज सकते हैं।

- LRS was launched on 4 February 2004 with an initial limit of USD 25,000.
- एलआरएस 4 फरवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था, जिसकी प्रारंभिक सीमा 25,000 अमेरिकी डॉलर थी।
- The present limit under LRS is USD 2,50,000 per financial year.
- वर्तमान में एलआरएस के तहत वार्षिक प्रेषण सीमा 2,50,000 अमेरिकी डॉलर है।

